A Daily News Magazine
इंदौर
सोमवार, 24 मार्च, 2025

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 163, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

पहली बात

'लाजवंती' न्याय-पालिका की आबरू पर काले साये

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में अग्निकांड के दौरान मिले जले-अधजले नोटों के जखीरे की खबरों के अफवाहों की राख में तब्दील हो जाने की दास्तान में कई सवाल गुंथे हैं। आग में जले बोरों में नोटों के आंकड़ों का पहला आकलन 15 करोड़ रूपए धीरे-धीरे सिकुड़ने लगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे दिल्ली हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के घर में मिली बड़ी रकम ने न्याय-पालिका में भ्रष्टाचार के सिरों को खोल दिया है। होली के मौके पर 14 मार्च की रात घटित अग्निकांड के दरम्यान मिले नोटों के इस जखीरे की कहानी अब परवान चढ़ने लगी है।

घटना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और निर्धारित इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर घटित घटनाओं के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैश मामले में अलग से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस बीच जस्टिस वर्मा का तबादला अलग प्रक्रिया है। यह तबादला स्वतंत्र है और आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रेस नोट में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में घटित घटनाओं के संदर्भ में गलत सूचनाओं और अफवाहों का हवाला गैर-मौजूं लगता है। गलत सूचनाओं और अफवाहों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की इस ताकीद के बाद हवा में कई सवाल तैरने लगे हैं। पहला सवाल है कि क्या यह बेआबरू होने से हैरान-परेशान लाजवंती न्याय पालिका के गैरतमंद तकाजों को बंद दरवाजों के पीछे दुरूस्त करने की कोई तदबीर है? दूसरा सवाल यह है कि अफवाहों का यह तिलिस्म क्या सरकार की आन-बान और शान में खलल पैदा करने वाले भ्रष्टाचार के कारनामें को परदों के पीछे ढकेलने की कोशिशों का प्रयास है?

भ्रष्टाचार के आपराधिक घटनाक्रमों में दागों को धोने के लिए गलत सूचनाओं और अफवाहों की मासूम अपीलों और दलीलों का इस्तेमाल आजमाया हुआ सर्वकालिक औजार है। यह औजार राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अलग-अलग रूप में कामयाब भी होता रहा है। सच को विघटित और विगलित करने के लिए अफवाहों और गलत सूचनाओं की केमेस्ट्री कारगर मानी जाती है। अफवाहों के माध्यम से तथ्यों में ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है, जो सच्चाइयों के आगे कई बखेड़े खड़े कर देते हैं। कोशिश यह होती है सच पीछे सरकता जाए और अफवाहों की जमीन पुख्ता होती जाए।

देश मे कार्य पालिका, विधायिका और न्याय पालिका के बीच विश्वसनीयता के इंडेक्स में ज्युडिशयरी का ग्राफ अभी भी सर्वोच्च पायदान पर है। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अफवाहों और सूचनाओं के स्याह धुंध से न्यायपालिका को बचाना पहली जरूरत है। यही वजह थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां जले नोटों का जखीरा मिलने की घटना के बाद लोग उद्वेलित और उत्तेजित नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच न्यायपालिका के गलियारों में भ्रष्टाचार का यह विस्फोट हताशा के भाव गहराने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभूतपूर्व पैमाने तय किए हैं। पैमाने आश्वस्त करते हैं कि इस जांच में सच आहत नहीं होगा।

देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर इन तथ्यों की पुष्टि की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला है। सुप्रीम कोर्ट की वेब-साइट पर जले-अधजले नोटों के फोटो इस बात की ताकीद है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी घटनाओं को रोकने के मामले में संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से उनके सरकारी बंगले के कमरे में मौजूद पैसे और नकदी का हिसाब मांगा है। यह वीडियो दिल्ली पुलिस ने हाय कोर्ट को दिया है। तस्वीरों और वीडियो में एक दमकलकर्मी प्लास्टिक की थैलियों में जले हुए नोटों की गड्डियां निकालता हुआ दिख रहा है। एक व्यक्ति नोटों पर लगी गांधी तस्वीर की हवाले से यह कटाक्ष करता भी दिख रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई है।

जस्टिस वर्मा वीडियो से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह मुझे फंसाने और मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश प्रतीत होती है। उनका कहना है कि ''मैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात पर ध्यान दें कि जिस परिसर में हम रहते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम परिवार के तौर पर करते हैं, वहां से कोई मुद्रा बरामद नहीं हुई है।''

नकदी की बरामदगी के बारे में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया गौरतलब है। धनखड़ की प्रतिक्रिया समूची कार्य प्रणाली को उजागर करने वाली है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस मसले पर ध्यानाकर्षण के बाद उनसे अनुरोध किया गया था कि इस मामले में वो कुछ निर्देशात्मक टिप्पणी करें। लोकतंत्र में न्यायिक उत्तरादायित्व बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के साथ आगे आने के लिए सरकार को आवश्यक और विशिष्ट निर्देश दें। जगदीप धनखड़ ने कहा कि- नकदी की कथित बरामदगी के मुद्दे पर मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि यह घटना घटने के बाद तत्काल सामने नहीं आई। अगर ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से जुड़ी होती तो वह तत्काल निशाना बना दिया जाता।

उपराष्ट्रपति ने ऐसे मामलों में सभी के लिए ऐसी पारदर्शी, जवाबदेह, और प्रभावी प्रणालीगत प्रक्रिया की आवश्यकता प्रतिपादित की, जो समदर्शी सिस्टेमेटिक रिस्पांस के तहत काम करे। सभापति ने कहा कि वो सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष से संपर्क करके इसी सत्र में इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा का मैकेनिज्म तलाश करेंगे। महाभियोग के मामले में सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों का प्रतिवेदन मिला है। इसके सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई करने में उन्हें सुविधा होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि आम लोगों में न्याय-पालिका के प्रति विश्वास बना रहे।

वैसे देश की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में सात दिनों तक इतने बडे घटनाक्रम का गुमशुदा रहना अचरज पैदा करता है। यह गुमशुदगी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की उन चिंताओं को संपुष्ट करती है कि न्याय पालिका की देहरी पर गोपनीयता का तंत्र सक्रिय है, जिसे लांघना आसान नहीं है। तर्क यह है कि यदि किसी नौकरशाह, राजनेता, मीडियाकर्मी, वकील अथवा व्यापारी के नोटों का यह जखीरा मिलता तो क्या देश भर कुहराम मचाने वाली सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर के सीनियर अधिकारियों की भूमिका इतनी खामोश और खबरदार होती? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हायकोर्ट के न्यायाधीशों को प्राप्त विशेषाधिकार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं।

कैश की 'आग' में बुरी तरह झुलसे जस्टिस यशवंत वर्मा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपने सरकारी आवास में आग लगने के दौरान मिले कैश को लेकर घिरते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेज और डेटा शामिल हैं, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द विवाद लगातार सामने आ रहा है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए एक बयान में नकदी बरामदगी की घटना में उन पर लगे आरोपों

का खंडन किया। जस्टिस वर्मा ने बताया, उनके स्टाफ में से किसी को भी मौके पर मौजूद कैश या मुद्रा के कोई अवशेष नहीं दिखाए गए। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने पर्सनली अपने स्टाफ के साथ इस मामले की जांच की, जिन्होंने पुष्टि की कि घर में कथित रूप से पाए गए नोटों को हटाया नहीं गया था। केवल मलबा और बचाए जा सकने वाले सामान ही हटाए गए थे। ये घर में अलग से रखे हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच, पुलिस कमिश्नर ने कथित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचित किया है कि जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड के अनुसार, 15 मार्च की सुबह कुछ मलबा और आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट जारी की फोटो-वीडियो वेबसाइट पर डाले

सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी है। साथ ही तीन तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थीं। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा।

नई करवट ले रहा है बिहार, वहां एनडीए की सरकार होना जरूरी

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर भोपाल में बनेगा पॉर्क, लगेगी प्रतिमा : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, बिहार शासन के मंत्री श्री राजू कुमार सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' अभियान के तहत आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार नई करवट ले रहा है। ऐसे में देश में और बिहार में एनडीए की सरकार होना जरूरी है। भगवान राम और कृष्ण के नाम से ही हमारी संस्कृति चलती है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा भगवान राम और कृष्ण का रास्ता रोकते रहे हैं। इन्हीं लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान आडवाणी जी की रथयात्रा को रोका था।

सदियों पुराना है मध्यप्रदेश और बिहार का नाता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भले ही 1912 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन मध्यप्रदेश से उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। मौर्य काल में जब सम्राट पाटलिपुत्र में बैठते थे, तो भावी सम्राट अवंतिका में बैठकर शासन व्यवस्था संभालते थे। उस काल में सम्राट अशोक ने भी अपने जीवन के 10 वर्ष अवंतिका में बिताए थे। विधर्मियों ने जब राजा भोज के साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो यहां के लोगों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बिहार में ही शरण ली थी। हमें यह बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि भोजपुरी बोली भी राजा भोज से संबंधित है। बिहार के क्षत्रियों में उज्जैनिया ठाकुर के नाम वाली भी एक शाखा है, जो उज्जैन से बिहार के घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करती है।

पहले पूर्वी मेदिनापुर, अब कोलकाता दौरा भी रद्द

ईद के कारण अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा फिर टला

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संगठन की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले थे। उनका यह दौरा कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि अमित शाह का 29-30 मार्च का दौरा प्रस्तावित थी लेकिन फिलहाल वह बंगाल नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे ईद होना बताया जा रहा है। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को 29 मार्च की रात कोलकाता पहुंचना था। उन्हें 30 मार्च को पार्टी की कई संगठनात्मक बैठकों में भाग

लेना था। 30 की रात तक कई कार्यक्रमों और मीटिंग में भाग लेने के बाद रात में उन्हें दिल्ली वापस लौटना था। सुकांत मजूमदार ने बताया कि ईद के त्योहार के कारण दौरा स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन निश्चित रूप से वह (अमित शाह) बहुत जल्द राज्य का दौरा करेंगे।

सुप्रभात

मैं वर्तमान के पीछे आकर
खड़ा हो गया हूं चुपचाप
यहीं कहीं उन सारे दृश्यों की बुनियाद है
जो दिखायी पड़ते रहते हैं हमारे
चारों ओर
इतिहास के अंत :करण से
उपजी लपटों से ही मारा
जायेगा यह
भस्मासुर
यहीं छिपा है अंगार
जो उड़ा सकता है उसके
सारे आयुध
भंडार
यहां कोई माचिस नहीं है,
कोई तीली
भी नहीं
अरणिमंथन करना होगा मुझे
तब तक घिसनी पड़ेंगी लकड़ियां, जब तक
धुंआ न उठने लगे
मैं चुप रहूंगा
जो भी बोलना होगा,
बोलेगी बस चिनगारी।

- सुभाष राय

काव्य, नाट्य और फिल्म की त्रिवेणी से सराबोर उत्सव

विक्रमोत्सव

डॉ. जफर महमूद
उज्जैन से

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमोत्सव अंतर्गत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से उज्जैन का टावर चौक काव्य रसधारा से सराबोर हो उठा। देशभर से पधारे ख्याति प्राप्त कवियों ने ओज, वीर, हास्य और श्रृंगार से भरपूर अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने अपने चुटीले अंदाज में दर्शकों को खूब हंसाया। दिल्ली से आई श्रृंगार रस की कवयित्री कीर्ति काले ने अपनी मधुर रचनाओं से समां बांधा।

फिल्म गीतकार शेखर अस्तित्व, संजू फेमा (मुंबई), सुदीप श्रोला (जबलपुर) और सुरेश अलबेला (मुंबई) ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोहा। ओज और वीर रस से सराबोर कविताओं की प्रस्तुति अशोक चारण ओज (जयपुर) और गौरव चौहान (इटावा) ने की, जबकि भक्ति रस के कवि पं. सात्विक नीलदीप (अयोध्या) ने अपने काव्य पाठ से श्रद्धा का भाव जगाया। गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प (बड़नगर) ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्यपरिषद सदस्य राजेश कुशवाह, वरिष्ठ पुराविद डॉ. रमण सोलंकी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कवि दिनेश दिग्गज ने किया।

विक्रम नाट्य समारोह में 'श्रीकृष्ण तुम कब आओगे' का मंचन- विक्रम नाट्य समारोह में दूसरी शाम जयंत देशमुख निर्देशित नाटक -श्रीकृष्ण तुम कब आओगे' का प्रभावी मंचन विजय हुआ।नाटक मूलतः दिनकर जोशी के दो उपन्यासों 'श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते' और 'द्वारिका का सूर्यास्त' पर आधारित है। प्रस्तुति में दिखाया गया कि एक तरफ महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप से यादव कुल का नाश और दूसरी तरफ मदिरा में लिप्त कृष्ण पुत्र सांब के उपहास के बाद महर्षि कश्यप का श्राप कि यादव कुल का संहार होगा। दोनों श्राप को सहज स्वीकार कर जब श्रीकृष्ण अपने वंश का नाश कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात किस तरह हर पात्र जैसे सत्यभामा, द्रौपदी, अश्वत्थामा, अक्रूर आदि अपने आप को दोषी मानते हैं, कृष्ण को कष्ट देने के लिए। यह नाटक वसुदेव, देवकी, बलराम, कंस के जीवन के अनछुए पहलूओं को उजागर करता है। अर्जुन की पीड़ा, दारूक की स्वामी भक्ति, उद्धव की मित्रता और राधा के निश्छल प्रेम को दर्शाता है। हर पात्र की चाह है कि श्याम एक बार फिर मिल जाते।

कृष्ण की भूमिका को समय मोदी और बाल कृष्ण को हर्षवर्धन टिक्का ने जीवंतता दी। गांधारी के किरदार को शमीम खान ने बखूबी निभाया। बलराम बने विभाष कुमार और रुक्मिणी को प्रियंका कश्यप ने जीवंत कर दिखाया। जयंत देशमुख के सशक्त निर्देशन में कलाकारों ने नाटक कोअभिनय के साथ वेशभूषा, रंग कल्पना, आलोकन, अकल्पन और प्रभावी संगीत के सम्मिश्रण से सफलतापूर्वक मंचित किया।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन 9 फ़िल्में प्रदर्शित - विक्रमोत्सव के अंतर्गत पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव (आईएफएफएएस) में दूसरे दिन नाइजीरिया के उच्चायुक्त एच.ई. उबोंग अकपन जॉनी, प्रथम सचिव अलखुले वुराओला सेनामी, डिप्लोमेट अटैची बशीर उस्मान उपस्थित थे। इस अवसर पर उबोंग अकपन जॉनी ने कहा कि भारत के प्राचीन शहर उज्जैन की दुनिया में अलग पहचान है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है विशेष रूप से भाषा, कला साहित्य और फिल्म जैसे माध्यम संस्कृतियों को विस्तार देते हैं। फिल्म समारोह में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का आभार भी व्यक्त किया। समारोह के दूसरे दिन विभिन्न भाषाओं की 9 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

जिसमें भारतीय भाषाओं में 'गोपाल श्रीकृष्ण (1965)', 'बलराम श्रीकृष्ण', 'श्रीकृष्ण लीलालू (तेलगू)', 'राधा कृष्णा (बंगाली)', 'श्रीकृष्ण शरणम् (गुजराती)', 'श्रीकृष्ण रूकमणि सत्यभामा (कन्नड़)' व 'श्रीकृष्ण विजयन (तमिल)' शामिल हैं। विदेशी भाषाओं में 'जूलिया हेश अ सुगर(2024)' एवं 'वन वीक एंड अ डे' हैं। विदेशी फिल्में इंग्लिश सबटाइटल वर्जन के साथ दिखाई गईं।

देशमुख लोकायुक्त के डीजी, साई मनोहर को गुप्तवार्ता का प्रभार, राजपूत रीवा आईजी बनाए गए

भोपाल। राज्य सरकार ने बजट सत्र के बीच करीब 15 आईपीएस अधिकारियों की तबादला नयी पदस्थापना दी हैं। गृह विभाग के देर शाम जारी आदेश के अनुसार सीनियर आईपीएस आदर्श कटियार को स्पेशल डीजी प्रशासन, सोनाली मिश्रा एडीजी को चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय के साथ पीटीआरआई का अतिरिक्त प्रभार, रवि कुमार गुप्ता एडीजी रेल, संजीव शमी एडीजी दूरसंचार, आशुतोष राय एडीजी अजाक, राजाबाबू सिंह एडीजी प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय, ए साई मनोहर वर्तमान दायित्व के साथ एडीजी गुप्तवार्ता, चंचल शेखर एडीजी विसबल, जयदीप प्रसाद एडीजी एससीआरबी पुलिस मुख्यालय, योगेश देशमुख एडीजी लोकायुक्त संगठन, राकेश गुप्ता एडीजी संचालक खेल एवं युवक कल्याण, गौरव राजपूत आईजी रीवा, श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु सचिव गृह, साकेत प्रकाश पांडे डीआईजी पुलिस मुख्यालय और राजेश सिंह डीआईजी रीवा बनाया गया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार,24 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

महिलाओं के बार में काम करने पर बंगाल में बवाल

● भाजपा ने इजाजत देने के खिलाफ निकाली बड़ी रैली

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा की महिला शाखा ने शनिवार को कोलकाता में एक रैली निकाली। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक के पारित होने का विरोध किया गया। भाजपा महिला प्रकोष्ठ की नेता फाल्गुनी पात्रा ने दावा किया कि

तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सत्तारूढ़ सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। यह रैली उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से लेकर करीब 2 किलोमीटर दूर बउबाजार स्थित आबकारी विभाग मुख्यालय तक निकाली गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में संशोधन करते हुए महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत देने वाला विधेयक पारित कर दिया। पात्रा ने कहा, 'राज्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

शहीद भगत सिंह ने वैज्ञानिक समाजवाद की आवश्यकता पर जोर दिया

भोपाल। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में 'भगत सिंह के क्रांतिकारी चिंतन का महत्व' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन शाकिर सदन में किया गया।

वरिष्ठ साहित्यकार कॉमरेड इकबाल मसूद ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि 'भगत सिंह केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक गंभीर विचारक भी थे।' उन्होंने समाज में वर्गीय शोषण के खिलाफ वैज्ञानिक समाजवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।

विषय प्रवर्तन करते हुए कॉमरेड सत्यम पांडे ने कहा कि 'भगत सिंह ने जिस सामाजिक न्याय और समानता के सपने को देखा था,' उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आज भी हमारे कंधों पर है। भगत सिंह का क्रांतिकारी चिंतन अन्याय के हर रूप के खिलाफ प्रतिरोध की प्रेरणा देता है।

संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड डी. डी. शर्मा ने कहा कि 'भगत सिंह ने धर्म, जाति और सांप्रदायिकता के खिलाफ वैज्ञानिक सोच' को अपनाने की बात की थी। आज समाज में बढ़ती असमानता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में उनके विचारों को अपनाना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि आज के युवा आंदोलन को भगत सिंह के विचारों से सीखकर सामाजिक बदलाव के लिए सक्रिय होना चाहिए।

कार्यक्रम में शिवशंकर मौर्य, सचिन श्रीवास्तव, नवाब उद्दीन, बालकृष्ण नामदेव, अरविन्द सक्सेना ,फिदा हुसैन, बी. पी. मिश्रा, रमज़ान खान, लाखन सिंह रघुवंशी, शंकर राव, शेर सिंह सहित अन्य प्रगतिशील विचारधारा के साथी उपस्थित रहे।

अब पंजाब में रात को नहीं रुकेंगी हिमाचल की बसें

● एचआरटीसी का बड़ा फैसला,20 रूट पर बंद की सर्विस

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने पंजाब के चार जिलों में 20 रूट पर अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को घोषणा की कि जब तक भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, तब तक आम आदमी पार्टी शासित राज्य में रात में वाहन पार्क नहीं किए जाएंगे। यह घोषणा अमृतसर में खड़ी चार एचआरटीसी बसों के शीशे क्षतिग्रस्त करने

और उनमें से एक पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के एक दिन बाद हुई है। अमृतसर में पुलिस ने कहा कि घटना के समय वाहनों के अंदर कोई मौजूद नहीं था और मामले की जांच चल रही है। शिमला में एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने कहा कि जिन बसों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें रात भर अमृतसर में खड़ा रखा गया था और उन्हें आगे बिलासपुर, देहरा और ऊना के लिए रवाना किया गया।

संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर गिरफ्तार

● जफर अली को सुबह घर से उठाया,4 घंटे पूछताछ, इलाके में फोर्स तैनात

संभल (एजेंसी)। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया।

करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की। जफर अली को अब चंदौसी कोर्ट ले जाया गया है। वहीं, जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए।

जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर दूर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात

किए गए हैं। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद इलाके में पहुंच गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दंगा भड़काने की साजिश रचने में जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी।

इसी मामले में एसआईटी प्रभारी कुलदीप सिंह, एसीपी (उत्तरी) श्रीचंद्र और सीओ संभल अनूप चौधरी उनसे सवाल-जवाब किए। इससे पहले, हिंसा के एक दिन बाद यानी 25 नवंबर को पुलिस ने जफर को उठाया था और कोतवाली में उनसे पूछताछ की थी। वकील की यूनिफॉर्म में थे जफर अली गिरफ्तारी के बाद जफर अली को करीब रैपिड रिएक्शन फोर्स के 50 जवानों और पुलिस वालों की सुरक्षा में पुलिस जीप में बैठाया गया। गिरफ्तारी के समय जफर अली अपनी अधिवक्ता की पोशाक में थे। उन्होंने काले कोट को अपने हाथ में ले रखा था। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद वह जीप में बैठ गए। जिस समय जफर अली को चंदौसी की कोर्ट द्वितीय ले जाया जा रहा था, सड़क के दोनों साइड जवान तैनात थे।

भारत भी बनाएगा 6 पीढ़ी के जेनरेशन लड़ाकू विमान

ट्रायल फेज में पहुंच गया है एएमसीए का जेट प्रोग्राम, होगा ताकतवर

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफ-47 एनजीएडी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए 20 अरब डॉलर का शुरुआती बजट लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग को दिया है। इस बजट में इस फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, जिसके तहत इंजन का निर्माण किया जाएगा, नये कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, एवियोनोमिक्स समेत कई तरह के डेवलपमेंट्स और किए जाएंगे। यानि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है, जिसके पास अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चीन भी जे-36 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर चुका है। दावे किए गये हैं कि जे-36 एक छठी पीढ़ी

के लड़ाकू विमान होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत में अभी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट भी कम से कम 10 साल दूर है।

लिहाजा भारत दुविधा में फंसा हुआ है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानि आईडीआरडब्ल्यू ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि भारत की भी योजना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की है। अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर खुलासा किया है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि एयरफोर्स के अधिकारी ने ये भी बताया कि इस तरह के एडवांस विमान बनाने की किसी भी योजना के लिए नए सिरे से डिजाइन की आवश्यकता होगी और फिलहाल भारत की क्षमताओं के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग होगी।

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी

● पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा,13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य

आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रह रहा है। ये बेल्जियम के एंटवर्प शहर में रेजीडेंसी कार्ड पर रह रहें है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद 2018 में भारत से एंटीगुआ-बरबूडा भाग गया था। चोकसी को भारत लाने के लिए अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है।

मोदी सरकार को छू भी नहीं पाएगा परिसीमन का मुद्दा !

● पहली ही बैठक में बिखर गया विपक्ष, टीएमसी का किनारा

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और वह बीजेपी सरकार को दक्षिण विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनका कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही दक्षिण को भारी नुकसान होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर शिवार को उन्होंने चेन्नई में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। ओडिशा और पंजाब के

अलावा दक्षिणी राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि हिंदी बेल्ट और महाराष्ट्र के दलों ने पहली ही बैठक में किनारा कस लिया। वहीं टीएमसी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे में इस बैठक से यह भी पता चल गया है कि परिसीमन के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। डीएमके ने इसी मुद्दे पर यह बैठक रखी थी।

सरकारी वकील दे दीजिए, मां-बाप नहीं लड़ेंगे मेरा केस

मुस्कान ने जेलर से लगाई गुहार, नशे के बिना हालत खराब

मेरठ (एजेंसी)। दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के दिन अब जेल में कट रहे हैं। बताया गया कि जेल में भी वे नशे के लिए तड़पते रहे। वे खाना भी नहीं खा रहे हैं। वहीं जेल प्रशासन ने नशा छुड़वाने के लिए दवाइयों और काउंसलिंग का सहारा लिया है। सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने बताया कि उन्हें अलग-अलग बैरक में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुस्कान का परिवार केस लड़ने को तैयार नहीं है ऐसे में सरकारी वकील के लिए न्यायालय को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया, तीन दिन पहले मुस्कान और साहिल को जेल में लाया गया था। आते ही वे कहने लगे कि उन्हें पास की बैरक में रखा जाए। हालांकि साफ तौर पर बता दिया गया था कि जेल में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक पुरुष और महिला बैरक का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ऐसे में दोनों को अलग-अलग रखा गया है। जब भी कोई बंदी आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। पाया गया कि वे नशे के आदी हैं। कारागर मे नशा नहीं मिल सकता। उन्हें दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनकी काउंसलिंग हो रही है और योग, मेडिटेशन में लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि आम कैदी उनसे दूर रहें और बार-बार

उनके केस के बारे में ना पूछें। उन्होंने बताया, मुस्कान ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने उसे बुलाया तो उसने कहा कि घर वाले उससे नाराज हैं। वे केस नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उसे सरकारी वकील दिलाया जाए। इसको लेकर एक पत्र न्यायालय को भेजा जा रहा है। कैदी का अधिकार है कि उसे वकील मिले और इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा, उन लोगों को जेल का सिस्टम पता नहीं था। महिला और पुरुष के बैरक आधा किलोमीटर दूर हैं। उन्हें समझा दिया गया तो वे मान गए। उन्होंने कहा, वे ड्रग्स की डिमांड तो नहीं कर रहे थे। हालांकि डॉक्टरों ने जानकारी दी कि वे नशा करते हैं।

नीतिश कुमार ने खोला तेजस्वी के लिए दरवाजा !

इफ्तार पार्टी के बहाने भेज दिया न्यौता, कुछ मुस्लिम संगठन करेंगे बॉयकाट

पटना (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार रविवार को पटना में अपने आवास पर एक बड़ी दावत-ए-इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। इस इफ्तार में कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और बड़े नेता शामिल होंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। लेकिन, कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में इस इफ्तार का बायकॉट करने का फैसला किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतिश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते हैं। इस साल भी वे यह परंपरा निभा रहे हैं। यह इफ्तार पार्टी रविवार शाम को 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाया गया है।

राजद नेता तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत बुलाया गया है। अब यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस इफ्तार में शामिल होते हैं या नहीं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उनके आने की संभावना कम है। इफ्तार में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। जदयू, भाजपा, हम, लोजपा (रा) और रालोमा के नेता भी इसमें भाग लेंगे। इस बीच, बिहार के कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस इफ्तार का बायकॉट करने का ऐलान किया है। इन संगठनों ने नीतिश कुमार को एक पत्र लिखकर बताया है कि वे वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से जदयू में हलचल है। बायकॉट करने वाला संगठन बिहार, झारखंड और उड़ीसा का एक बड़ा मुस्लिम संगठन है।

बैंकॉक में मोदी का अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं मोहम्मद यूनुस

● भारत नहीं दे रहा है भाव, एस जयशंकर ने बताई पूरी कहानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांगलादेश के अस्थायी सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस आगामी बैंकाक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अनुरोध भारत से कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत ने उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब एक संसदीय पैनल ने बैठक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है। गौरतलब है कि यह बैठक इस शनिवार को संसदीय परामर्श समिति की पहली बैठक के रूप में आयोजित हुई थी, जिसमें कई सांसदों ने बांगलादेश में हिंदू

समुदाय पर हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत द्वारा इस संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में सवाल किए। बैठक में एस जयशंकर ने सांसदों को बताया कि ढाका में अस्थायी सरकार ने दावा किया है कि बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और इन्हें माइनॉरिटी टार्गेटेड नहीं माना जाना चाहिए। जयशंकर ने सांसदों को बांगलादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर भी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान और चीन के मामलों पर बाद में बात करने का संकेत दिया और इस बैठक में इन मुद्दों को अलग से उठाने की बात की। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि एससीओ (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) पाकिस्तान के रवैये के कारण निष्क्रिय हो गया है और इसीलिए भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। जयशंकर ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री बैंकॉक सम्मेलन में भाग ले सकते हैं।

औरंगजेब पर 'संघ', हमारा आइकॉन कौन हो, सोचना जरूरी

सरकार्यवाह होसबाले ने कहा-हमलावर सोच देश के लिए खतरा

बेंगलुरु (एजेंसी)। देश में इस समय औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकॉन हो सकता है। देश का आइकॉन कोई बाहरी होगा या फिर कोई और। इस पर चिंतन की जरूरत है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिन की बैठक का रविवार को आखिरी दिन था। इसके बाद होसबाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद को लेकर बयान दिया। वहीं, होसबाले ने कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण पर भी

सवाल उठाया। उन्होंने कहा- डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आरक्षण को लेकर बिल पास किया है। कर्नाटक में भाजपा शासन के दौरान सरकार पर संघ का दबाव था। क्या मंत्रियों के निजी सहायक के रूप में संघ के पदाधिकारियों को की नियुक्ति के लिए दबाव बनाया जाता था। इस पर होसबाले ने कहा- नियुक्ति के लिए कभी दबाव नहीं डाला गया। आरएसएस के शताब्दी समारोह को लेकर होसबाले ने कहा- आरएसएस का शताब्दी वर्ष कोई उत्सव नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और समाज को संगठित करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर है। उन्होंने 2025-2026 के लिए संघ के कार्यक्रमों की भी घोषणा की।

संक्षिप्त समाचार

संभागायुक्त श्री गुप्ता ने खाचरोद के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. पाटीदार को निलंबित किया गया

उज्जैन (निप्र)। संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता ने उज्जैन जिले के खाचरोद के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. भूपेंद्रसिंह पाटीदार को श्री नंदराज गोधाम गौशाला लेकोड़िया के नोडल अधिकारी के तौर पर पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि के दौरान डॉ पाटीदार का मुख्यालय जिला कार्यालय उपसंचालक पशुपालन रहेगा।

देवास जिले की 98 टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायते आज होगी पुरुस्कृत

देवास (निप्र)। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में वर्ष 2024 में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले की कुल 98 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। निर्धारित मानदण्ड अनुसार जिले मे 98 ग्राम पंचायतों में से 23 सिल्वर एवं 75 ब्रॉज के लिये चयन हुई है। इन सभी चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सीएचओ को 24 मार्च 2025 को प्रातः 11.00 बजे से जिला पंचायत कार्यालय जिला देवास में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

शासकीय विधि महाविद्यालय देवास में विश्व जल दिवस का आयोजन

देवास (निप्र)। शासकीय विधि महाविद्यालय देवास में महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के द्वारा 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार चौहान ने पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव-जंतुओं एवं प्रकृति के लिए जल के महत्व को बताते हुए जल संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम की संयोजक एवं प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. भारती जोशी ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में जल की बचत के प्रकारों की जानकारी दी। महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र श्री दरियाव सिंह मालवीय ने बताया कि मनुष्य के शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा जल ही है एवं जल संरक्षण एवं संचय की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय का स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं तथा अन्य सम्बधित उपस्थित थे।

निवेदन अभियान जागरूकता से पॉलिथीन मुक्त होगा ओंकारेश्वर

खण्डवा (निप्र)। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में ओंकारेश्वर में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा निवेदन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दल बनाकर दुकानदारों को और वहाँ के रहवासियों को ,बाहर से आने वाली जनता को समझाइश दे रही हैं कि वह पॉलिथीन का उपयोग न करें। पॉलिथीन की जगह ,कपड़े की या कागज की बनी हुई थैलियां ही उपयोग करें ।ताकि ओंकारेश्वर को पॉलिथीन मुक्त बनाया जा सके और ओंकारेश्वर जैसे पवित्र स्थल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर लगातार दुकानदारों से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी राजेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा बताया गया कि ओंकारेश्वर को पॉलिथीन मुक्त बनाना है इसी उद्देश्य से जागरूकता के लिए अभियान के रूप में विभाग कार्य कर रहा है क्योंकि 1 अप्रैल से ओंकारेश्वर में पूर्णतः पॉलिथीन प्रतिबंधित रहेगा इसलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है।

कुष्ठ से मुक्ति के लिये चिकित्सक अपना योगदान दें : डॉ. जुगतावत

खण्डवा (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से जिले में कुष्ठ मुक्ति की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें सभी चिकित्सक अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्ष्य सामुहिक प्रयासों से ही हासिल किये जा सकते हैं। कार्यशाला में जिले में पदस्थ सभी पेथियों के चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डॉ. जुगतावत ने कहा कि चिकित्सकों के कंधों पर जन स्वास्थ्य की बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी विभाग की सभी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी है, चिकित्सक अपना दायित्व निष्ठा और इमानदारी से निभाएं।

इंदौर में चलेगा जल गंगा जल संरक्षण अभियान

नये तालाब बनेंगे, पुराने तालाबों, बावड़ियों तथा कुँओं का होगा जीर्णोद्धार, सघन वृक्षारोपण भी किया जायेगा, मंत्री श्री सिलावट की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

इन्दौर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार इंदौर जिले में जल गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर नये तालाब बनाये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुँओं का जीर्णोद्धार कराया जायेगा। साथ ही सघन वृक्षारोपण भी होगा। इसके लिए जिले में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। यह अभियान 30 मार्च से प्रारंभ होकर आगामी 30 जून तक सतत चलेगा। यह जानकारी आज यहाँ जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, विधायक सुश्री उषा ठाकुर, श्री मनोज पटेल तथा श्री मधु वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भारत सिंह पटेल, श्री श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान जन-जन के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। 'जल है तो कल है', जल से आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। जल चिन्ता व चिंतन दोनों का विषय है। जल हमारी धरोहर है। हमारी संस्कृति एवं परंपरा में जल और वृक्षों की पूजा का बड़ा महत्व है, इसको देखते हुए इस अभियान को बेहतर और प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना होगा। इस अभियान समाज के हर वर्ग की भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जायेगा। हमारा प्रयास होगा की यह अभियान एक आदर्श और अनुकरणीय हो तथा देश में नम्बर वन बनें। बैठक के पश्चात अतिथियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि इस अभियान को सभी के सहयोग से जन आंदोलन के रूप में चलाया जायेगा। अभियान में जल संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत शुरूआत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले तालाबों, जल स्त्रोतों तथा देवालयों में जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। जल गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत 30 मार्च 2025 से की जायेगी। इस अभियान में जल स्त्रोतों और देवालयों की सफाई की योजना बनाई जाएगी। यह संतों, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित होगा, जिसमें मशीन, सामग्री व श्रम का समुचित नियोजन किया जाएगा । कार्य पूर्ण होने पर वरुण पूजन और जल अभिषेक होगा तथा रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों को दी जाएगी।

बनेंगे 19 नये अमृत सरोवर : जिले में गत वर्ष चलाये गये अभियान के तहत 101 नये अमृत सरोवर बनाये गये थे। इन सरोवरों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान में अमृत सरोवर 2.0 के तहत 19 नए तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपये व्यय होना संभावित है । अब तक 10 स्थलों का चयन हो चुका है, जबकि शेष का चयन 30 मार्च 2025 तक वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा ।

तालाबों से हटेंगे अतिक्रमण : अभियान के तहत राजस्व विभाग के साथ तालाबों का सीमांकन किया जायेगा। राजस्व अभिलेखों में नवीन तालाबों को दर्ज किया जायेगा। तालाबों पर अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। तालाबों की सीमा को दर्शाने हेतु चॉदे-मुनारे बनाये जायेंगे। तालाबों का जन भागीदारी से गहरीकरण होगा । मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से तालाब का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। तालाबों में जल की आवक बढ़ाने के लिये इनलेट क्षमता बढ़ायी जायेगी। तालाबों के पास पौधारोपण होगा । उपयोगकर्ता समूह बनाकर संधारण एवं रख रखाव किया जायेगा।

नदियों के स्त्रोत के कैचमेंट पर होंगे कार्य : जिले की महत्वपूर्ण नदियों के स्त्रोत से वाटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किये जायेंगे । रिमोट सेंसिंग और फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर कार्ययोजना बनाकर एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण किया जाएगा । गेबियन संरचना, ट्रेंच, वृक्षारोपण, चेकडेम तालाब आदि कार्य समुदाय की भागीदारी से किये जायेंगे।

पूर्व निर्मित जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार : पूर्व में उपयोगी रहे लेकिन वर्तमान में अनुपयोगी चेकडेम व स्टॉप डेम का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर जीर्णोद्धार की कार्ययोजना तैयार कर कार्य किये जायेंगे। गाद निकालने में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कुँओं की मुण्डेर को सुव्यवस्थित किया जायेगा।

वृहद वृक्षारोपण : महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्षाकाल में वानिकी व उद्यानिकी पौधरोपण के लिए पारंपरिक जल स्त्रोतों के निकट भूमि का चयन किया जाएगा। पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समीपस्थ नर्सरियों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें एसएचजी संचालित नर्सरियों को प्राथमिकता मिलेगी।

युवाओं को जलदूत बनाया जायेगा : प्रत्येक ग्राम से 1-2 युवा महिला या पुरुष का चयन कर जलदूत बनाया जायेगा । ये जलदूत जीर्णोद्धार, सफाई, शासकीय योजनाओं में हितग्राही चयन और जल के सदुपयोग हेतु जनजागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेंगे । जलदूतों का पंजीकरण भी किया जाएगा ।

कलेक्टर की पहल पर नवाचार के तहत ऑनलाइन व्यवस्था बनाया गया नया पोर्टल

इन्दौर (निप्र)। इंदौर जिले में नयी कॉलोनियों को विकसित करने की अनुमति और कॉलोनाईजर के लायसेंस के लिए अब किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इधर-उधर भी नहीं भटकना होगा। कॉलोनियों की विकास अनुमति और कॉलोनाईजर के लायसेंस के लिए आवेदन लेने और अनुमति जारी करने और लायसेंस देने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह की पहल पर नवाचार के तहत ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन परमिशन सिस्टम(क्रॉप्स) इंदौर नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। यह जानकारी आज यहां कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, क्रेडाई के श्री संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य कॉलोनाईजर, डेवलपर्स, संबंधित विभागों के अधिकारी आदि मौजूद थे। बैठक में सभी ने कलेक्टर श्री आशीष सिंह के इस नवाचार की सराहना की और कहा कि इससे विकास अनुमति और लायसेंस प्राप्त करने में बेहद सुविधा होगी। हमें इधर-उधर नहीं भटकना होगा। काम सहजता के साथ होगा। समय की बचत भी होगी। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि यह ऑनलाइन व्यवस्था एक अभिनव व्यवस्था है। कॉलोनाईजर और डेवलपर्स के लिए बेहद मददगार होगी। कॉलोनाईजर और डेवलपर्स के सुझाव और उनके अनुभव के आधार पर पोर्टल को ओर अधिक बेहतर तथा सुविधाजनक बनाया जायेगा।

निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता और आवेदकों की संतुष्टि के साथ किया जाये राजस्व प्रकरणों का निराकरण : कलेक्टर

राजस्व प्रकरणों के आवेदकों से फोन पर लिये गए फीडबैक में आवेदक की असंतुष्टि और खराब गुणवत्ता मिलने पर तहसीलदारों के विरूद्ध होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

इन्दौर (निप्र)। इंदौर जिले में आवेदकों की संतुष्टि के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में नवाचार के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवेदकों से उनका फीडबैक लेने और संतुष्टि का स्तर पता करने के लिए सुशासन संवाद केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस केन्द्र के माध्यम से लिये गये फीडबैक में आवेदकों की असंतुष्टि और खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित तहसीलदारों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जायेगी।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज यहां सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी पूरी लगन, मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के साथ पारदर्शी रूप से कार्य करें। सभी अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करें। प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। प्रकरण विस्तृत आदेश के साथ निराकृत करें। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही तथा उदासीनता नहीं बरतें। उदासीनता और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही तथा उदासीनता बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री राजेन्द्र रघुवंशी, श्रीमती निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने विवादित तथा अविवादित नामांतरण और बटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाये। सीमांकन के प्रकरण निराकरण होने के तुरंत पश्चात आवेदक को फील्ड बुक दी जाये। पुराने लंबित सीमांकन के प्रकरण तुरंत निराकृत करें। फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाये। उन्होंने आरआरसी के प्रकरण भी निराकृत करने की निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जारी वित्तीय वर्ष के कुछ ही दिन शेष है, इसको देखते हुए डायवर्सन सहित अन्य राजस्व वसूली को तेज करते हुए लक्ष्य पूर्ण करें।

ग्रीष्मकालीन मूंग में नींदानाशक का प्रयोग नहीं करने के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

देवास (निप्र)। उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों द्वारा आमदनी बढ़ाने के लिए तीसरी फसल के तौर पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, विदिशा, सीहोर, नरसिंहपुर, रायसेन समेत कई जिलों में लगनग 14.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग लगाई जा रही है। देवास जिले में मुख्यतः खातेगांव, कन्नौद, सतवास तहसील में 45000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग ली जाती है, जो 70 से 80 दिनों में फसल तैयार होती है, लेकिन तब तक मानसून आ जाता है। जिससे मूंग फसल खराब होने की संभावना रहती हैं। किसानभाई ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर चवला, उडद व मक्का की बोवनी कर सकते हैं। किसानभाई मार्च के अंतिम सप्ताह तक मूंग फसल की बोनी कर दें। बारीश से फसल खराब न हो, इसके लिए किसान रासायनिक नींदानाशक का उपयोग करते हैं। इससे उपज तो प्रभावित होती ही है, साथ ही मृदा शक्ति (कृषि भूमि की स्वास्थ्य) भी कमजोर कर देती है। यहीं कारण है कि सरकार और कृषि वैज्ञानिक इससे चिंतित है और जागरूकता कार्यक्रम चलाने जा रही है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन मूंग छह से आठ हजार रुपये प्रति किंटल की दर से बिकती है। किसानों के लिए यह अतिरिक्त आय का बड़ा माध्यम है। सिंचाई सुविधा के विस्तार के कारण किसान बड़े पैमाने पर मूंग की खेती करने लगे हैं। सरकार इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीदती है। लेकिन जिस तरह में फसल में कीटनाशक का उपयोग किसान कर रहे हैं, यह उपज की गुणवत्ता के साथ-साथ भूमि की मृदा शक्ति एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। खाने लायक नहीं रहती मूंग कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग 70 से 80 दिनों की फसल है लेकिन इसे 20 से 25 दिन पहले ही पका लिया जा रहा है। दरअसल, किसानों को डर होता है कि वर्षा हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हानिकारक रसायन ग्वाइफोसेट, पेराक्वाट का उपयोग करके उसे जल्द पका लिया जाता है। कीट और खरपतवार से फसल के बचाव के लिए कीटनाशक और नींदानाशक का उपयोग अत्याधिक मात्रा में किया जाता है। कुल मिलाकर यह उपज खाने लायक नहीं रहती। इससे गंभीर बीमारियां हो रही हैं। किसान भी इस जहरीली मूंग के बारे में वाकिफ हैं, इसलिए ये लोग इसे स्वयं के उपयोग के लिए नहीं रखते हैं। मानव और पशु-पक्षियों के लिए हानिकारक फसल जल्दी पकाने के लिए किसान कीटनाशक के साथ पेराक्काट डायक्लोराइड का छिड़काव करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु-पक्षियों पशु के लिए हानिकारक है।

महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में द्वितीय दिवस राष्ट्रीय वर्कशॉप रिसर्च मेथाडोलॉजी का समापन

धार (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रथम सत्र में संबोधित करते हुए डॉ विनोद सेन सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक विषय रिसर्च एथिक्स ने कहा कि हमें नैतिक रिसर्च का निर्माण करना चाहिए क्योंकि अगले 40 वर्ष तक राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे लोगों के रूप में काम करेगा एवं जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी होना चाहिए साहित्य में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। इस सत्र की समीक्षा डॉक्टर प्रतीक्षा पाठक ने की।

डॉ आर बेंजामिन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्मेंट का इंग्लिश भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू विषय मैकेनिज्म ऑफ़ रिसर्च ने कहा कि आप जो भी रिसर्च करते हैं उसे कोई न कोई जरूर पड़ता है सारे कौवे काले होते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ कौवे सफेद भी हो सकते है । आज के जमाने के हिसाब से रिसर्च होना चाहिए, नहीं तो आपकी थीसिस कचरे के ढेर में पड़ी रह जाएगी। आप ऐसी रिसर्च कीजिए जो पूरे समाज में पढ़ने लायक हो बच्चा जन्म से सीखता है गर्भ से नहीं । संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं हम तो बहुत कम जान पाते हैं इस सेशन की समीक्षा डॉक्टर जे के सागोरे ने की ।

डॉ नेतराम गौरव सहायक प्राध्यापक भौतिक गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर विषय - रिसर्च टूल पर विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि रिसर्च का टॉपिक तो हम तीसरी चौथी पांचवी की किसी किताब का फ्रंट पेज को देख ले तो भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है । उन्होंने पब मेट इस्कोपस इंडेक्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऐन लिस्ट, शोध सिंधु इन फ्लिबनेट, शोधगंगा, विद्वान, गूगल स्कॉलर, फ्री फुल पीडीएफ, इंस्टीट्यूशन आईडी,एस सी आई हब, डी आई ओ, रिसर्च गेट वे, कंसोर्टियम टरनिटी आदि रिसर्च टूल्स के बारे में भी बताया । इस सत्र की समीक्षा डॉक्टर सुलोचना पाटिल ने की अंत में आभार डॉक्टर गजेंद्र उज्जैनकर ने माना। यह जानकारी डॉ निर्भय सिंह सोलंकी एवं आई टी प्रभारी डॉ ताराचंद नरगावे, डॉ मीरा जामोद ने दी। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी इंचार्ज पीएम उषा डॉ जे के सागोरे, संयोजक डॉ प्रभा सोनी, समन्वयक श्री प्रकाश तिलक जिला कोऑर्डिनेटर सेडमैप है । इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर आयशा खान डॉक्टर आरसी घावरी डॉक्टर एम एल चौहान एवं समस्त स्टाफ उपस्थित था ।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा धन्यवाद यात्रा निकाली गई

बाबा महाकाल की कृपा से पूरे शहर में धार्मिक वातावरण निर्मित है और शराब बंदी के निर्णय से हम सब उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं

उज्जैन (निप्र)। धार्मिक स्थलों पर शराब विक्रय का पूर्ण प्रतिबंध पर मा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी द्वारा ऐतिहासिक निर्णय को लेकर धर्म प्रेमी जनता के साथ-साथ संत समाज, शहरवासियों और विशेष कर महिलाओं में हर्ष व्याप्त है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आज धन्यवाद यात्रा एवं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई । जो निरंतर स्वैच्छिक संगठनों के के माध्यम से शहर के अलग-अलग स्थान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता ने सहभागिता निभाकर इस निर्णय के पक्ष में अपना समर्थन दिया है।

परिषद के विकासखंड समन्वयक अरुण व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद पार्क से प्रारंभ हुई धन्यवाद यात्रा घास मंडी चौराहा,माधव नगर हॉस्पिटल,गुरुद्वारा एवं इंदिरा गांधी चौराहा होते हुए शहीद पार्क में संपन्न हुई। यात्रा का शुभारंभ नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव ने झंडी दिखाकर किया। संभाग शिव प्रसाद मालवीय जय दीक्षित जिला समन्वयक, अतिथियों ने यात्रा को ध्वज दिखाकर रवाना किया गया

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर निगम सभापति महोदया द्वारा मा .मुख्यमंत्री जी के

निर्णय की प्रशंसा की एवं शहर में धार्मिक वातावरण निर्मित होगा साथ ही शराब बंदी से उज्जैन नगरी को धार्मिक नगरी मान्यता मिलेगी। बाबा महाकाल की कृपा से पूरे शहर में धार्मिक वातावरण निर्मित है और शराब बंदी के निर्णय से हम सब उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं सनातन धर्म की रक्षा तथा लोगों में धार्मिक भावना का जागरण होगा।

शिव प्रसाद मालवीय संभाग समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने कार्य योजना एवं परिचय बताते शराबबंदी के निर्णय के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे चौपाल संवाद निबंध प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजित किया जा रहे हैं उसी क्रम में यह यात्रा का आयोजन किया है।धन्यवाद यात्रा आयोजन में ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय,शासकीय नर्सिंग कॉलेज,आशा कार्यकर्ता,गायत्री परिवार,जन शिक्षण संस्थान,परिषद की नवांकुर संस्थाएं संकल्प समर्थ ऑर्गेनाइजेशन व ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति दताना,देवी अवंतिका सामाजिक युवा कल्याण संस्था, इनीशिएटिव समिति,संवाद शोध संस्थान, सुरभि जन कल्याण समिति, देव संजीवनी सामाजिक कल्याण संस्था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग,शिप्रा उपभोक्ता संरक्षण संस्था,खादी ग्रामोद्योग महिला उत्थान समिति, मां हरसिद्धि समग्र उत्थान,श्री हरि शरणम समिति ग्राम विकास प्रस्फुटन एवं मेंटर की अहम भूमिका रही। यात्रा में परिषद के नेटवर्क से जुड़े छात्र-छात्राओं, प्रस्फुटन समिति सदस्यों व सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ शहर की धर्म प्रेमी जनता ने भी सहभागिता निभाई।

संपादकीय

किसान आंदोलन का ये हश्र

पिछले हफ्ते पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सवा साल से आंदोलनरत किसानों को राज्य की भगवंत मान सरकार ने जिस तरह बुलडोजर चलाकर बेदखल किया, उससे जहां आम जनता को राहत मिली है, वहीं यह भी साबित हो गया है कि किसान आंदोलन कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के लिए अपने हित साधने की फुटबॉल बन गया है। जो विपक्ष में रहता है, वो किसानों का समर्थन करता है और सत्ता मिलते ही किसानों को उनकी हैसियत दिखाने में कोताही नहीं करता। जिस बीजेपी ने किसान आंदोलन पार्ट वन में किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही बीजेपी अब पंजाब में आप की मान सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आप पर किसानों को धोखा देने का आरोप जड़ दिया है। और इसमें सच्चाई भी है। आज से तीन साल पहले दिल्ली में आप और उसके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कृषि कानूनों का विरोध में आंदोलन पर बैठे किसानों के बड़े हितैषी के रूप में खुद को पेश कर रहे थे, क्योंकि वह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ था। लेकिन जब वही किसान पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें बदले में बुलडोजर और लाठियां मिलीं। पंजाब पुलिस ने न केवल आंदोलनकारियों के डेरे तंबू उखाड़ फेंके बल्कि यह इंतजाम भी कर दिया कि किसान फिर से सार्वजनिक रस्ता रोकने की हिम्मत न करें। हालांकि किसान कितना मानेंगे, कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लाखों रहवासियों ने बड़ी राहत महसूस की है, जो रास्ते बंद होने से 13 महीने से भारी परेशानी झेल रहे थे। और कोई होता तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर रास्ता खाली कराती, लेकिन चूंकि मामला किसानों का था, इसलिए बार बार बातचीत की बात कही जा रही थी। मान सरकार का तर्क है कि किसानों द्वारा हाईवे की नाकेबंदी के कारण प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई आवश्यक थी। वैसे किसानों की जो मुख्य मांग है, वो है सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी। यह गारंटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, भले ही विपक्ष में रहकर राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहती रहें। दूसरे, जो लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वो वास्तव में कितने किसान हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर 13 महीने तक धरने बैठा रह सकता है? जाहिर है कि आंदोलनकारी किसान दरअसल वो हैं, जिनके पेट भरे हैं और उनके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा कुछ आंदोलनजीवी तत्व हैं, जो देश में असंतोष की मशाल को हमेशा जलती रखना चाहते हैं। तीसरे, किसान आंदोलन की राजनीतिक ताकत को भी सियासी पार्टियों ने समझ लिया है। तीन साल पहले हुए लंबे किसान आंदोलन के बाद देश के तीन राज्यों और लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इसमें किसान आंदोलन का असर कहीं भी नजर नहीं आया। यहां तक कि जिस पंजाब और हरियाणा राज्यों में किसानों की नाराजगी का बड़ा खतरा समझा जा रहा था, वहां भी चुनाव नतीजों पर किसानों की नाराजी का कोई असर नहीं दिखा। किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के छतरी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब विस चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीत सका। यहां तक कि अधिकांश की जमानत जब्त भी हो गई। ऐसे में सवाल उठा कि ये आंदोलनकारी किसान हैं कौन और किसानों पर इनका कितना प्रभाव है? ये किसानों के हितैषी हैं या फिर उनके दुश्मन?

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

नीतीश कुमार के 'अनियमित' व्यवहार के राजनीतिक पहलू

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है। इस टेंशन की वजह विपक्षी दल नहीं बल्कि सरकार में प्रमुख सहयोगी दल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का अप्रत्याशित और 'अनियमित' व्यवहार जारी रहने के कारण भाजपा 'किंकर्तव्यविमूढ़' है । बताया जाता है कि भाजपा का एक धड़ा उनके 'खराब स्वास्थ्य' के नतीजों को लेकर चिंतित है। हालांकि पार्टी उनके नेतृत्व में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है।

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं जहां पहुंचने का नसीब विरलों को ही मिलता है। फिलहाल देश की समकालीन राजनीति में देखें तो अजातशत्रु कहलाने का दावा केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। खुद लालू परिवार आज चौतरफा नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है। पर नीतीश कुमार का साथ पाने के लिए परिवार के लोग अलग विचार रखते हैं। नीतीश कुमार तमाम विरोध के बावजूद अपने विरोध के स्तर को कम से कम लालू परिवार के लिए बहुत निचले स्तर पर नहीं ले जाते हैं। जबकि आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म होने के बाद एक दौर ऐसा था तेजस्वी कितने दिनों तक एक्स पर लगातार नीतीश के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे। नीतीश कुमार देश के एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनके पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर शुभचिंतक हैं। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को धरातल पर लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। जब से नीतीश कुमार ने इंडिया गुट को छोड़ा तब से लगातार यह गठबंधन कमजोर होता गया।यह नीतीश के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि सिर्फ 2 परसेंट सजातीय वोट के साथ वे बिहार की राजनीति में 3 दशकों से सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बने हुए हैं।

इस सबके बावजूद किसके दिन कब फिरते है और कब वह विवादों के घेरे में फंस जाता है कहा नहीं जा सकता। नीतीशकुमार भी कुछ समय से विवादों के घेरे में है। ताजा विवाद गुरुवार को पटना में हुआ। सेपक टकराव विश्व कप 2025 के उद्घाटन के बाद राष्ट्रगान की घोषणा होने पर कुमार अचानक मंच से उतर गए और प्रतिभागियों से हाथ मिलाने लगे। बाद में जब राष्ट्रगान बजा तो वे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। राष्ट्रगान का अपमान करने के कारण कुमार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके इस हालिया कृत्य ने खूब वाहवाही बटोरी और विपक्षी दलों, राजद और कांग्रेस को आगामी राज्य चुनावों में इसका फायदा उठाने का मौका दे दिया, उनका तर्क है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें एक और कार्यकाल नहीं दिया जा सकता।

सूत्रों ने कहा कि भाजपा को जेडीयू और एलजेपी के साथ एक और कार्यकाल जीतने का भरोसा है, लेकिन पार्टी की चिंता यह है कि सार्वजनिक रूप से कुमार के अप्रत्याशित व्यवहार ने अक्सर विरोधियों को मौका दिया है। हालांकि, पार्टी का मानना है कि कुमार एक मूल्यवान भागीदार बने रहेंगे और आरजेडी के 'जंगल राज' की यादें 'सत्ता विरोधी भावना' की किसी भी संभावना को खत्म कर देंगी।

नीतीशकुमार का व्यवहार एक समान नहीं रहा है। ऐसे दिन भी आए हैं जब कोई दुर्घटना नहीं हुई और वे नियंत्रण में दिखे, जैसे कि उनकी 'प्रगति यात्रा' के दौरान, भले ही वे कई दिनों तक लोगों की नजरों में रहे हों। लेकिन ऐसे भी दिन आए जब कुमार ने इस तरह का व्यवहार किया कि उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया और उनके समर्थकों को इसे सही ठहराना मुश्किल हो गया। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपने उतार-चढ़ाव भरे तरीकों से उबरेंगे।

राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने शुक्रवार को उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथ में है। भारती ने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं दिखे। मैं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको उनकी मानसिक स्थिति ठीक लगी। वह हर दिन महिलाओं, बच्चों का अपमान करते रहते हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथ में है।

कहा तो यहाँ तक जाता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। वे अपने को बीमार भले न बताएं या मानें, पर यह सत्य अब छिपा नहीं है। पटना में चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के वक्त होने वाले राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार की असामान्य हरकत सबने देखी ऐसी घटनाएँ लंबे समय से चली आ रही इस आशंका की पुष्टि हुई कि वे मानसिक तौर पर सहज और सचेत नहीं हैं। उनकी बीमारी का पहला संकेत तो उसी दिन सार्वजनिक हो गया था, जब दो साल पहले उन्होंने अपने जनता दरबार में खुद को ही खोजना शुरू किया था। वे बार-बार अपने अधिकारियों से गृह मंत्री को बुलाने की जिद कर रहे थे। अधिकारी भी हतप्रभ थे। किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि जिसे आप खोज रहे हैं, वह तो आप खुद हैं। नीतीश कुमार ही सीएम की जिम्मेवारी के साथ गृह मंत्री भी हैं। अधिकारियों और नीतीश के करीबी नेताओं ने इतना भर ही किया कि जनता दरबार का सिलसिला रोक दिया गया।

नीतीश कुमार के बारे में लोगों की यह आम धारणा रही है कि वे गंभीर नेता हैं। नपे-तुले और सधे शब्दों में अपनी बातें रखने वाले नीतीश के स्वभाव में अचानक आए इस परिवर्तन को विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार की हरकतों को राष्ट्रगान का अपमान माना है और इसे राष्ट्रवाद से जोड़ कर उन्हें कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को बीमार बता कर उनका उपहास उड़ा रहे हैं। लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के स्वर में जरूर व्यंग्यात्मक सहानुभूति दिखती है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब सीएम पद छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने बेटे निशांत को ही सीएम बना देना चाहिए।

भाजपा नेताओं की बोलती अब बंद है। जेडीयू नेता भी समस्या की गंभीरता का हल निकालने के बजाय नीतीश को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते वक्त वे भूल जा रहे हैं कि इसे न नीतीश कुमार के साथ उचित व्यवहार कहा जा सकता है और न बिहार की जनता के साथ यह न्याय ही है। नीतीश कुमार को बेहतर इलाज की जरूरत है, न कि बचाव की। भाजपा को भी साफ मन से यह सोचने की जरूरत है कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखना अच्छा नहीं। जेडीयू का दुर्भाग्य यह है कि नीतीश कुमार अब तक जेडीयू में सुप्रीमो की भूमिका में रहे हैं। उनके बारे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं। नीतीश के इर्द-गिर्द रहने वाले अधिकारी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं।

बहरहाल, भाजपा के सामने यह भी सचाई है कि बिहार में आज की तारीख में कम सीटों के साथ सरकार चलाने की ताकत किसी में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास भाजपा से कम विधायक हैं। इसी तरह आरजेडी से भी जेडीयू के विधायक कम हैं। पर भाजपा हो या आरजेडी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी नीतीश कुमार की ओर ही देखते हैं। यह नीतीश कुमार का जादू ही है कि अगर वो एक बार आरजेडी के साथ जाने की बात कर दें तो उनकी सभी गलतियों को परिवार माफ कर देगा।आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा हो या जेडीयू-आरजेडी किसी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके चलते नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा सके। नीतीश अगर बीमार हैं तो भी अन्य नेताओं के मुकाबले उनकी स्थिति बेहतर है। इसलिए उनके रिजाइन करने की बात बेमानी हो जाती है।आरजेडी भले ही मांग कर रही है कि नीतीश कुमार रिजाइन कर दें। पर आरजेडी नेताओं को पता है कि नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा लेता है तो वो उनके लिए और मुश्किल होनी तय है।

विश्व राजनीति

प्रेरणा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी-अर्थशास्त्र की अध्येता हैं।

किसके हाथ में है, 'ट्रम्प कार्ड'

लोग 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धांत में भरोसा करते हैं वे ट्रम्प की बड़ी लाठी के सामने घुटने टेक, हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन इस सिद्धांत को चुनौती देने वाले भी हैं जो ट्रम्प के सामने खड़े हैं। वैसे न यह दृश्य नया है, न यह परिस्थिति ! दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब विजेता 'मित्र राष्ट्र' ऐसे ही माहौल में अपने- अपने हित में दुनिया का बंटवारा करने बैठे थे तब भी ऐसा ही नजारा था। तब कितने देशों का स्वाभिमान कुचला गया, कितनों का भूगोल बदल दिया गया व दुनिया की छाती पर, बंदूक की ताकत से एक नया देश बनाकर रख दिया गया - इसराइल ! दुनिया दो शक्ति-ध्रुवों में बांट दी गई और सबको मजबूर किया गया कि सब अपनी-अपनी पक्षधरता घोषित करें - कौन अमरीकी छतरी के नीचे है, कौन सोवियत संघ का दामन थामे है।

ऐसी दुनिया में एक तीसरा आदमी खड़ा हुआ - जवाहरलाल नेहरू ! उसने भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से सारी दुनिया से कहा-हम किसी गुट में नहीं हैं ! हम गुटनिरपेक्ष हैं ! हम न अमेरिका के साथ हैं, न रूस के; हम आपके 'शीतयुद्ध' का हिस्सा बनने से इंकार करते हैं। हम अपने और दुनिया के तमाम लोगों के हक व स्वाभिमान से जीने के अधिकार की पैरवी करते हुए, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। नेहरू ने इसे अपने निजी साहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एशियाई मुल्कों की आवाज में बदल दिया - फिर तो सुकार्णो भी आए; मार्शल टीटो भी; नासेर भी आए ! दुनिया की कूटनीति का चेहरा बदलने लगा।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्वबैंक और 'अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष' (आइएमएफ) ने दुनिया का सारा व्यापार अपनी मुट्ठी में कर लिया था। गरीब देशों को कुछ छोटी-मोटी रियायतें देकर, बदले में उनके सारे बाज़ारों पर क़ब्ज़ा कर लिया था, लेकिन समय का पहिया घूमा। दादाओं के नियमों की काट निकालकर कई देश आगे आए। चीन उनमें एक था। वह अपने रास्ते चलता हुआ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब वह अमेरिका को अपदस्थ करने की राह पर चल पडा है।

अमेरिका को चीन व आर्थिक रूप से मजबूत होते दूसरे देशों का मुकाबला करना भारी पड़ रहा है। वह चाह रहा है कि इन्हें इतना परेशान करे कि ये घुटनों के बल आ जाएं। इसके लिए उसने 'व्यापार-दर' (टैरिफ) को अपना हथियार बनाया है। उसने घोषणा कर दी है कि आप अपने देश में अमेरिकी सामानों पर जितना 'आयात-कर' लगाते हैं, अमेरिका भी आपके यहां से आने वाले सामानों पर उतना ही 'आयात-कर' लगाएगा। यह दलील कि आप अपने देश के किसानों और लघु उद्योगों को बचाना चाहते हैं, कोई मानी नहीं रखती। वे तो अमरीका का हित भर देखेंगे, क्योंकि उन्हें 'अमेरिका को फिर से महान' बनाना है।

अब रास्ता एक ही है कि आप अमरीकी सामानों व कंपनियों के लिए अपने बाजार खोल दें या फिर वह आपके लिए दरवाज़े बंद कर देगा। दुनिया के कई देश हैं जो अमेरिका को बेचते ज्यादा और उससे ख़रीदते कम हैं। इस कमाई को 'व्यापार-घाटा' (ट्रेड डेफ़िसिट) कहते हैं। आज की तारीख़ में अमेरिका का सबसे बड़ा 'व्यापार-घाटा' चीन के साथ है जो लगभग 300 बिलियन डॉलर का है। उसके बाद 'यूरोपियन यूनियन' और मैक्सिको, जापान, कनाडा, भारत आते हैं। इनके साथ क्रमशः 235, 172, 69, 63, 46 बिलियन डॉलर का 'व्यापार- घाटा' अमेरिका उठाता है। अमेरिका के साथ कुछ देशों का 'व्यापार-बचत' का भी सम्बन्ध है। इसमें नीदरलैंड के साथ लगभग 45 बिलियन डॉलर, आस्ट्रेलिया के साथ 16 और इंग्लैंड के साथ 11 बिलियन डॉलर का 'ट्रेड सरप्लस' है।

विश्व-व्यापार में अमेरिका सबसे बड़ा आयातकर्ता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका के लिए भारत से व्यापार 9वें स्थान पर आता है, पर भारत के लिए अमेरिका से व्यापार पहले स्थान पर आता है। वैसे तो यह सच्चाई बिना आंकड़ों के भी साफ-साफ दिखाई देती है, लेकिन आंकड़े हमें समझा देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौदेबाज़ी में किसकी लाठी सबसे बड़ी व मजबूत है।

ऐसे में ज़रूरी है कि हम समझ लें कि आने वाले दिनों में भारत कहां-कहां सौदेबाज़ी कर सकेगा और किन-किन क्षेत्रों में उसे घुटने टेकने होंगे। आंकड़े बताते हैं कि भारत की आयात-दरें औसतन 17 प्रतिशत हैं, जबकि अमेरिका की केवल 3.3 प्रतिशत। कृषि क्षेत्र में यह अंतर और भी बढ जाता है। कृषि आयात पर भारत में सामान्यतः औसतन 39 प्रतिशत आयात-दर है, जबकि अमेरिका में 5 प्रतिशत। इसी तरह ग़ैर-कृषि क्षेत्र में यह क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत है। भारत अपने घरेलू क्षेत्र के संदर्भ में संरक्षण की नीति अपनाता रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में पिछले दशक में लगातार बढ़ोतरी ही देखी गयी है, लेकिन कोविड के बाद इसमें बड़ा उछाल आया। 2013-14 में जो व्यापार लगभग 62 बिलियन डॉलर का था, वह 2022-23 में लगभग 125 बिलियन डॉलर पहुंच गया- ! भारत की कोशिश है कि यह 2030 तक 500 बिलियन तक पहुंचाया जाय, लेकिन ट्रम्प इस व्यापार का समीकरण पूरी तरह बदलना चाहते हैं। भारत से अमेरिका के लिए मुख्यतः मोती, सस्ते हीरे, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है और अमेरिका से कच्चा तेल और उसके कई उत्पाद, हीरे और क़ीमती पत्थर, न्यूक्लीयर रिएक्टर, इलेक्ट्रिकल और चिकित्सा की मशीनें भारत को आयात होती हैं।

ट्रम्प भारत को 'आयात-दरों का बादशाह' (टैरिफ़ किंग) कहते हैं और भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि कुछ क्षेत्र, जो अब तक भारत ने अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखे थे, उसे अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। कांग्रेस में दिए भाषण में, ट्रम्प ने यह घोषणा कर दी है कि वे 1 अप्रैल 2025 से भारत पर उतना ही आयात-कर लगाएंगे जितना भारत लगाता है।

भारत के लिए ट्रम्प कृषि के क्षेत्र में गले की हड्डी बनेंगे, इसके आसार नजर आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी भारत के साथ अमेरिका का व्यापार-घाटा है, मतलब अमेरिका भारत से ज्यादा खरीदता है, जबकि भारत अमेरिका से कम मात्रा में खरीदता है। भारत से झींगा और प्रॉन, बासमती और अन्य चावल, सब्ज़ी के पौधे और अन्य पदार्थ, शहद और अन्य खाने-पीने की चीजें निर्यात होती हैं। बदले में अमेरिका से बादाम, रुई, एथेनॉल, सोयाबीन तेल, पिस्ता, मोटे अनाज से बने कॉर्नफ्लैक्स जैसी वस्तुएं आयात होती हैं।

अमेरिका के सेव पर भारत में 50 प्रतिशत आयात शुल्क था, जो अभी हाल में 15 प्रतिशत कर दिया गया है। दूध के पावडर पर आज भी भारत में 60 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। दूध से बने उत्पाद जैसे कि ताजा चीज़ और दही पर 30 प्रतिशत का आयात शुल्क है। नाश्ते में खाए जाने वाले कॉर्नफ्लैक्स और दूसरे डिब्बाबंद सामानों पर भी 30 प्रतिशत शुल्क है। अमेरिका में लोग मुर्गी के पंख - चिकन विंग्स - शौक से खाते हैं और टांगें बेकार जाती हैं।

इससे विपरीत भारतीय मुर्ग़े की टांग चाव से खाते हैं। अमेरिका की लम्बे समय से मांग रही है कि मुर्ग़े की वह टांग, जो उनके यहां बेकार जाती है, उसके लिए भारत का बाजार खोल दिया जाए, लेकिन आज भी भारत में पोल्ट्री के सामानों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क है। 'बोर्बन-व्हिस्की' पर भारत में सबसे ज़्यादा 150 प्रतिशत आयात शुल्क है।

पिछले दिनों भारत से आयात होने वाले श्रिंप पर अमेरिका ने आयात-शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते भारत का श्रिंप उद्योग घाटे में चल रहा है तथा जगह-जगह यह उद्योग बंद भी हो रहा है। यदि भारत से जाने वाले अन्य कृषि उत्पादों पर भी शुल्क लगा दिया जाए, जिसकी धमकी ट्रम्प लगातार दे रहे हैं तो हमारे कृषकों पर इसकी भारी मार पड़ सकती है। भारत के कृषि उद्योग के लिए आगे कुंआ, पीछे खाई-सी स्थिति बन रही है।

अमेरिका दुनिया को बड़े पैमाने पर मक्का, सोयाबीन और गेहूं बेचता है। भारत ने अपना बाजार इन सामानों के लिए बंद कर रखा है। इसी तरह अमेरिका और दुनिया की नजर भारत के डेयरी बाजार पर भी है। लम्बे समय से यह मांग रही है कि भारत अपना आयात शुल्क घटाए। गाय को बचाने में लगी बीजेपी सरकार के लिए ट्रम्प एक धर्म-संकट बनकर आए हैं। मोदीजी के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि घड़ी ट्रम्प साहब के पास है। हम और दुनिया उसकी टिक-टिक सुन रहे है। (सप्रेस)

सुप्रीम कोर्ट : सस्ता इलाज देने में सरकारें नाकाम

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढाँचा देने में नाकाम रही है। इससे निजी अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है। इसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार को गाइडलाईन बनानी चाहिए।

जस्टिस श्री सूर्यकांत और श्री एन. के सिंह की पीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि यह जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा दवाएं और मेडिकल सेवाएँ सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराएं, ताकि मरीजों का शोषण नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। हमारे देश में कोरोना के बाद से निजी अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। कोई देखने, सुनने वाला नहीं है। निजी अस्पताल में जब कोई मरीज पहुँचता है तो उसके परिवार के पास पर्याप्त राशि नहीं होने पर उसे अपना घर या खेत गिरवी रखना होता है, तब जाकर वे अपने परिवारजन का ईलाज करवा पाते हैं।

इतना ही नहीं, हर एक निजी अस्पतालों ने अपने अस्पताल में ही दवाई खरीदने की दुकान लगा रखी है। अस्पताल द्वारा मरीज के परिजन को दवा लिखने के बाद अस्पताल की ही फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। अस्पताल की मेडिकल शॉप मनमाने रेट पर दवाई देती है, जिसे खरीदना मरीज के परिजन की मजबूरी होता है।

सामान्यतः आमजन की रोजमर्रा की दवाई के लिए मेडिकल शॉप वालों से परिचय रहता है। इस कारण अपने नियमित मरीज को वह 10 से 20 प्रतिशत तक छूट भी दे देता है। किन्तु ऐसा निजी अस्पतालों में नहीं होता है। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि अस्पताल द्वारा लिखी गई दवाई उसी के मेडिकल शॉप पर ही मिलती है। अन्य मेडिकल शॉप पर वह दवाई उपलब्ध ही नहीं होती है। कई बड़े निजी अस्पतालों द्वारा फार्मेसी से ऑर्डर देकर दवाईयाँ बनवाकर उसे अपनी दुकान के लिए बुला ली जाती है और उसमें मनमानी एमआरपी लिख दी जाती है। यह एमआरपी सामान्य मूल्य से कई गुना अधिक कीमत की होती है, जिसे खरीदना मरीज के परिजनों के लिए मजबूरी बन जाता है।

दवाईयों की एमआरपी पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस कारण निजी अस्पतालों के मेडिकल शॉप से मिलने वाली दवाईयों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जरूरी दवाईयों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होना अत्यन्त आवश्यक है।

करीब डेढ़ साल पहले मध्यप्रदेश सरकार ने एक मनमाना आदेश निकाला। इस कारण प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की पैथालॉजी लैब निजी संस्थाओं को सौंप दी है। इसके दुष्परिणाम यह हुए कि पैथॉलॉजी लैब की जाँचों की दरों में 14 से लेकर 1108 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई। इसका बोझ सीधे-सीधे आमजन पर ही पड़ा।

उसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अब सरकारी अस्पतालों को भी निजी हाथ में देने की गतिविधि शुरू कर दी गई है। मध्यप्रदेश में 51 सिविल अस्पताल है। 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनमें से प्रथम चरण में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पीपीपी मोड पर 10 जिला अस्पतालों में निजी मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला कर लिया है। ये 10 जिला अस्पताल हैं- खरगोन, धार, बैतूल, टीकमगढ़, बालाघाट, कटनी, सीधी, भिंड, मुरैना आदि।

सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि निजी अस्पतालों की लूट और मेडिकल कॉलेजों की पैथालॉजी लैब को निजी हाथों में सौंपने के कारण आमजन की कितनी फजीहत होती है। यदि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को भी निजी हाथों में सौंप देंगे तो आमजन सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं से पूर्णतः वंचित हो जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि सरकारी अस्पतालों में ही सभी गंभीर बीमारियों का इलाज, जाँचें, चिकित्सा सुविधा, ऑपरेशन आदि की पर्याप्त सुविधाएँ मिल जाए, तो आमजन को निजी अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। कोरोना के बाद से तो निजी अस्पताल की बाढ़ सी आ गई है और सब निजी अस्पताल आमजन को लूटने में एक साथ है। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्य सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में ही पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की जाँचें और अधोसंरचना के साथ ही पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती कर दे तो आमजन को निजी अस्पतालों की लूट से बचाया जा सकता है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. हरीशकुमार सिंह

लेखक व्यंग्यकार हैं।

दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया

प्रदेश के एक बड़े राजनेता ने बात तो बड़े मार्के की कही है और जिस बात को कहने पर उन्हें शाबाशी देनी चाहिए उस बात के लिए उनकी लानत मलानत की जा रही है। वो क्या है कि आजकल कोई सच कहना नहीं चाहता और यदि कोई कह दे तो उसे ही घेर कर उसके द्वारा सत्य कहे गए वचन को वापस लेने या माफी माँगने के लिए आंदोलन किये जाते हैं। यही नहीं हालात इतने बदल गए हैं कि एक राजनेता को आप उसके कुकर्मों या कदाचरण के कारण गरिया दो तो वो कहेगा कि ये मेरा अपमान नहीं है बल्कि ये मेरी सम्पूर्ण जाति का अपमान है और उसकी जाति वाले भी उसके समर्थन में सड़क पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सच्चाई का जमाना नहीं है और अगर आप सच बोलोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।

तो बात उन राजनेता की हो रही थी जिन्होंने कहा कि भीख मांगना अच्छी आदत नहीं है और भिखारियों की फौज समाज को कमजोर कर रही है। राजनेता भी जानते हैं कि भीख मांगने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और भीख देना पुण्य का कार्य बताया गया है। फिर भीख मांगने से अहंकार कम होता है और प्राचीन काल में भिक्षाटन अनिवार्य रूप से कराया जाता था जिससे भीख मांगने वाले को दुनियादारी का पता चले। राजा बनने से पहले युवराज को देशाटन और बाकी को भिक्षाटन करना जरूरी था। भिक्षाम देहि कहकर रावण ने भी भीख मांगी थी। आज बेरोजगारी के विकट समय में भीख मांगना किसी बड़े रोजगार से कम नहीं है और हमारे शहर में तो पलासिया के भिखारी भी करोड़पति निकल रहे हैं और अपना रुपया ब्याज पर चलाते हैं। ये भिखारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं अन्यथा अपनी बैंक खोलकर, ऋण भी देने लगते। विदेशों में भीख मांगना एक कला है तो अपने यहाँ उद्योग। विदेशों में भीख सभ्यता से मांगी जाती है तो अपने यहाँ भिखारी असभ्यता के शिखर पर चढ़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। भीख लेने के लिए भिखारी अपनी मुद्राओं में काव्य के सभी नौ रसों का प्रयोग करने में नहीं चूकते। अविकसित देशों को विकसित मित्र देश, लड़ाई और सुरक्षा के लिए भीख में हथियार तक देते आये हैं।

तो इन राजनेता ने बात सौ प्रतिशत खरी कही है कि सरकार से भीख मांगना सही नहीं है क्योंकि सरकारें तो खुद रोज कर्ज लेकर, खुद भी घी पी रहीं हैं और जनता को भी रेवड़ियाँ बांट कर अपनी कुर्सी पक्की कर रही हैं। सरकारें जनता को सब कुछ तो फ्री में दे रही हैं फिर भीख मांगने की क्या जरूरत रह जाती है। शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर सब कुछ तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जनता को मुफ्त मिल रहा है फिर भी मंत्रियों के सामने अर्जियों के टोकरे क्यों भर देते हो। जब कुंभ जैसे विशाल मेले लगते हैं तो रोजगार भी मिल जाते हैं तो नौकरी की भीख क्यों मांगते हो। अरे भीख मांगने का अधिकार सिर्फ राजनेताओं को है जब वे पांच साल में लगभग रेंगते हुए, आपके घुटनों को छूते हुए वोट की भीख मांगते है और आप सब कुछ भुलाकर अपना बेशकीमती वोट देकर उन्हें जिता देते हैं और फिर ये जीतकर इन्हीं वोटों को रुपये में बदलने में लग जाते हैं और आपको भिखारी बताते हैं।

रही बात जनता के भीख मांगने की तो जनता को भिखारी बना कौन रहा है। सरकार जब दंभ भरती है कि वह अस्सी करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रही है तो यह अस्सी करोड़ जनता को आप खैरात में क्या दे रहे हैं जरा बताएं। और भीख तुम क्या दोगे, सरकार क्या भीख देगी जो खुद जनता के टैक्स से चलती है। इसलिए कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

सेंसरशिप के खिलाफ 'एक्स' की सरकार को चुनौती

भारत जैसे विशाल देश में इतनी विविधता और पहुंच के साथ सेंसर करना आवश्यक है। अनियंत्रित फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता की रक्षा करना भी आवश्यक है। साथ ही भारत की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को सुरक्षा उपायों की आवश्यक है। सेंसरशिप के माध्यम से सरकार ऑनलाईन उत्पीड़न और अश्लीलता को भी नियंत्रित करती है। ये सभी कदम बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाबालिगों को अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से रोकने में मदद करते हैं।

एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक कानूनी याचिका दायर की है। इसमें तर्क दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) और सहयोग पोर्टल का उपयोग एक गैरकानूनी और अनियमित तंत्र बनाता है जो वैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है। एक्स कॉर्प का तर्क है कि सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है। ऐसे आदेश जारी कर रही है जो धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015 के अपने एक फैसले में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए एकमात्र वैध कानूनी ढांचे के रूप में मान्यता दी है। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि सरकार धारा 69ए में उल्लेखित संरचित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, समानांतर सामग्री अवरोधन तंत्र बनाने के लिए उक्त धारा का उपयोग कर रही है।

आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत, सरकार के पास डिजिटल सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरूद्ध करने की शक्ति है, अगर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। हालांकि, इस प्रक्रिया को 2009 के सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके तहत अवरूद्ध करने के निर्णय लेने से पहले एक संरचित समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) के अनुसार, धारा 79(3)(बी) ऑनलाईन प्लेटफॉर्म को न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देती है।

यदि कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 79(1) के तहत अपनी 'सेफ हार्बर' सुरक्षा खोने का जोखिम होता है। इस आधार पर उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। 'सेफ हार्बर' का हिंदी में अर्थ है 'सुरक्षित बंदरगाह' या 'सुरक्षित आश्रय।' यह एक ऐसी कानूनी अवधारणा है, जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होती है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए प्लेटफार्म को कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराती है, जब तक कि वे आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या संबोधित करने के लिए कार्य करते हैं।

हालांकि, एक्स ने इस व्याख्या का विरोध किया है। इसके विरोध में यह तर्क दिया गया है कि प्रावधान सरकार को सामग्री को अवरुद्ध करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं देता है। इसके बजाय, इसने अधिकारियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से सेंसरशिप लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कानूनी चुनौती में एक और प्रमुख बिंदु सरकार के सहयोग पोर्टल का विरोध है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा बनाया गया यह प्लेटफॉर्म धारा 79(3)(बी) के तहत निष्कासन अनुरोधों को कारगर बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीधे संचार की सुविधा के लिए बनाया गया था। हालांकि, ''एक्स'' ने सहयोग पोर्टल पर एक कर्मचारी को शामिल करने से इंकार कर दिया है। उसने दावा किया कि यह एक सेंसरशिप टूल के रूप में कार्य करता है जो प्लेटफार्मों पर उचित कानूनी समीक्षा के बिना सामग्री को हटाने के लिए दबाव डालता है।

'एक्स' ने कहा कि 'मीटीई' अर्थात् भारत सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सहयोग नामक एक ऑनलाइन सेंसरशिप पोर्टल भी बनाया है। इस पर केंद्रीय और राज्य एजेंसियों और स्थानीय पुलिस अधिकारी धारा 69ए प्रक्रिया के बाहर धारा 79(3)(बी) के तहत अवरोधन आदेश जारी कर सकते हैं। एक्स ने कहा कि सेंसरशिप पोर्टल धारा 69ए के लिए एक अस्वीकार्य समानांतर तंत्र बनाता है। लेकिन, धारा 69ए की प्रक्रियाओं या सुरक्षा उपायों के बिना, संविधान, आईटी अधिनियम, अवरोधन नियमों और श्रेया सिंघल में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक्स से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है, जो अनुचित है।

'एक्स ने तर्क दिया है कि इन प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय, सरकार धारा 79(3)(बी) का उपयोग शॉर्टकट के रूप में कर रही है। इससे आवश्यक जांच के बिना सामग्री को हटाया जा सकता है। प्लेटफार्म इसे मनमाने ढंग से सेंसरशिप को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के प्रत्यक्ष उल्लंघन के रूप में देखता है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब बुधवार को केंद्र सरकार ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के साथ उसके एआई चैटबॉट, ग्रोक और इससे उत्पन्न होने वाली विवादास्पद प्रतिक्रियाओं पर चिंता जताई। ग्रोक, एक्स पर एक शक्तिशाली एआई चैटबॉट है। इसने हाल ही में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी अनफिल्टर्ड और अक्सर अनियमित प्रतिक्रियाओं के लिए भारत में लोकप्रियता हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ग्रोक द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रियाओं, जो गालियों से भरी हुई थी और चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा के बारे में एक्स से स्पष्टीकरण मांगा है। मुकदमे में तर्क दिया गया है कि यह न्यायिक निगरानी के बिना ऑनलाईन संवाद को नियंत्रित करने का सरकार का एक और प्रयास है।

एक्स कॉर्प ने अपनी याचिका में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। इसमें यह सहायता भी चाही गई है कि यह घोषित किया जाए कि धारा 79(3)(बी) सरकार को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है। साथ ही धारा 79(3)(बी) के तहत जारी सभी कंटेंट हटाने के आदेशों को अमान्य करने की भी प्रार्थना की है। यह सहायता भी चाही है कि अंतिम निर्णय आने तक सहयोग पोर्टल से आदेशों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करें तथा ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए एकमात्र वैधानिक तंत्र के रूप में धारा 69ए की पुष्टि करें। यह मामला ऐसे समय आया है जब भारत सरकार स्थानीय अधिकारियों को सीधे सीएसएएम रिपोर्टिंग के लिए नए पोर्टल सहयोग के साथ एकीकृत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव डाल रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले के अनुसार प्लेटफॉर्म को सीएसएएम की रिपोर्ट न केवल नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को करनी होगी। यह अमेरिकी कानून द्वारा अनिवार्य है। साथ ही पोक्सो अधिनियम के तहत भारतीय कानून प्रवर्तन को भी करनी होगी। आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के अनुसार, एक्स जैसे ऑनलाईन मध्यस्थ अपनी सुरक्षा खो सकते हैं यदि वे किसी उचित सरकारी एजेंसी द्वारा चिन्हित सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने में विफल रहते हैं। सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कामकाज के लिये महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि वे उन्हें उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री की मेजबानी से कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

श्रेया सिंघल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 69ए को सूचना अवरोधन शक्ति के रूप में केवल इसलिए बरकरार रखा। क्योंकि, यह कई सुरक्षा उपायों के साथ एक संकीर्ण प्रावधान है। धारा 69ए के विपरीत, धारा 79(3)(बी) में ये सुरक्षा उपाय और आवश्यकता मौजूद नहीं है। भारत में डिजिटल सामग्री पर सेंसरशिप ने व्यापक बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाओं और स्वतंत्र पत्रकारिता के उदय के साथ। डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप का मतलब है सरकार, संगठन या अन्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन कंटेंट पर नियंत्रण या दमन। इसमें वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक करना, सोशल मीडिया कंटेंट को हटाना, ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन तथा डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध सम्मिलित है।

भारत जैसे देश में इतनी विविधता और पहुंच के साथ सेंसर करना आवश्यक है। अनियंत्रित फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता की रक्षा करना भी आवश्यक है। साथ ही भारत की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। सेंसरशिप के माध्यम से सरकार ऑनलाईन उत्पीड़न और अश्लीलता को भी नियंत्रित करती है और स्पष्ट सामग्री, साइबरबुलिंग और गोपनीयता के उल्लंघन पर चिंताओं को भी संबोधित करती है। ये सभी कदम बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाबालिगों को अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से रोकने में मदद करते हैं। इस याचिका के माध्यम से एक्स कॉर्प ने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए, जिनका विभिन्न सामग्रियों की ऑनलाईन सेंसरशिप पर गंभीर असर हो सकता है। इसलिए उक्त याचिका के परिणाम को देखना आवश्यक होगा। इसका सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। इसका उद्देश्य फर्जी खबरों पर लगाम लगाना और नाबालिगों के लिए अनुपयुक्त सामग्री को सेंसर करना है।

विश्व टीबी दिवस पर विशेष

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार

टीबी मुक्त भारत अभियान की गति?

वर्ष-2030 तक हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से टीबी की बीमारी से मुक्ति का प्रण लिया हुआ है। उस निर्धारित अवधि में अभी 6 वर्ष शेष हैं। अभियान फिलहाल जिस अंदाज से जारी है, उससे प्रतीत होता है, लक्ष्य आसानी से पूरा होगा? अभियान की गंभीरता इसी बात से लगा सकते हैं कि आज 'विश्व टीबी दिवस' के मौके पर केंद्रीय स्तर पर 'टीबी मुक्त अभियान' की समीक्षा स्वंय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देश के टॉप चिकित्सकों के साथ करेंगे। तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर मंनसुख मावडिया ने पिछले साल 2024 को आज ही के दिन अभियान से जुड़े चिकित्सकों को एक टारगेट सौंपा था जिसकी समीक्षा उन्हें 2025 को विश्व टीवी दिवस पर करनी थी। फिलहाल वह अब स्वास्थ्य मंत्री की सीट पर नहीं हैं। उनकी जगह चिकित्सकों से वह रिपोर्ट मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लेंगे।

भारत में 'राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण' कार्यक्रम की शुरुआत तो वैसे साल-1962 में हुई थी। लेकिन कोशिशें कछुए की चाल जैसी आगे बढ़ीं। इसी कारण 1985 के बाद भारत में तपेदिक जैसी बीमारियों की बाढ़ आई। मुकम्मल तौर पर बीमारी पर नियंत्रण पाना सन-2001 से आरंभ हुआ था, जो 2010 तक कुछ सफलता मिली। वैश्विक जागरूकता के लिए ही टीबी दिवस सालाना 24 मार्च को मनाया जाता। इस रोग को चिन्हित सबसे पहले वैश्विक स्तर पर सन 1882 में किया गया। चिकित्सकों की रिसर्च ने टीबी के जीवाणु उसी दरम्यान खोजे थे। हालांकि, तब ये रोग आज की तरह जानलेवा नहीं आंका गया था। पर, धीरे-धीरे टीबी की बीमारी ने चिकित्सकों की रिपोर्ट को भी पीछे छोड़ा और अचानक से घातक हुई। सन् 1980 और 2000 का दौर टीबी बीमारी के नाम था। तब भारत में 26 लाख और पूरे संसार 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लोगों की मौते हुई थीं। इस आंकड़े ने संसार में कोहराम मचाया था। एक समय ऐसा था जब भारत में अन्य बीमारियों के मुकाबले टीबी सर्वाधिक थी। लेकिन प्रशंसा करनी होगी पूर्ववर्ती और मौजूदा केंद्रीय हुकूमतों की जिन्होंने समय रहते इस टीबी पर पार पाया।

सालाना केंद्रीय बजट में 'टीबी मुक्त अभियान' के लिए मोटा बजट आवंटन किया जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में पोलियो के बाद दूसरी बड़ी बीमारी टीबी ही रही। डब्ल्यूएचओं के मुताबिक टीबी की चपेट में सालाना पांच लाख अकाल मौते होती हैं। सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ी स्लो हुई है। इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकारी कोशिशों के अलावा जन सहयोग की अति आवश्यकता है। हमारे यहां टीबी के संबंध में वही पुरानी उक्ति 'परहेज इलाज से बेहतर है' चरित्रार्थ होती है क्योंकि टीबी के संक्रमण का प्रभाव हर आदमी पर नहीं पड़ता, यानी जिनका इम्मियून सिस्टम (रोगों से लड़ने की क्षमता) कमजोर है, वही टीबी की चपेट में आता है। शायद यही वजह है कि कुपोषण तथा पोषण तत्वों की कमी की वजह से गरीब और ग्रामीण आबादी टीबी से अधिक प्रभावित होती है।

टीबी को लेकर सर्तकता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, जो बीमारी घेरने से पहले आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। टीबी दूषित खानपान, प्रदूषण और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर फैलती है। यह न केवल फेफड़ों, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्से जैसे किडनी व दिमाग पर भी हमला करती है। इस पर काबू पाने के लिए पोलियो जैसी लड़ाई लड़नी ही होगी? वरना ये बीमारी यूं ही मुंह खोले खड़ी रहेगी। सामाजिक स्तर पर जनमानस को भी चेतना होगा? टीबी होने पर वैध-हकीमों के पास जाने के बजाय अस्पतालों में उपयुक्त इलाज कराएं। मौजूदा वक्त में प्रत्येक अस्पतालों में टीबी के लिए डॉट्स की व्यवस्था सुगम हैं। टीबी होना अब सामान्य खांसी बुखार जैसा हैं। टीबी किसी को भी, किसी उम्र में हो सकती है। लेकिन समय पर ईलाज अगर हो, तो ये बीमारी शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

टीबी से बचा कैसे जाए और इसका संक्रामक कितना घातक है, उसे बताने और समझाने के लिए ही 'विश्व टीबी दिवस' को आयोजित किया जाता है। ताकि इससे लोग विनाशकारी स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव के संबंध में जागरूक हो सकें। टीबी का मुख्य कारण तपेदिक माइकोबैक्टीरियम है जो कि एक छोटा, एरोबिक, चलने में अक्षम दण्डाणु है। वैसे, इस रोगजनक की उच्च लिपिड सामग्री उसकी अपनी अनूठी नैदानिक विशेषताओं के लिए ही जिम्मेदार है। भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बेंगलुरु में है और 'राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान' चेन्नई में स्थित हैं जहां रोजाना टीबी पर नई-नई रिसर्च होती हैं। इस बीमारी के आंकड़े निश्चित रूप से अभी भी डरावने हैं। भारत 2023 और 2024 के बीच 25.5 लाख टीबी रोगियों और 26.07 लाख मामलों को अधिसूचित करने में सक्षम रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है। डब्ल्यूएचओ की वैश्विक टीबी रिपोर्ट-2024 में भारत में टीबी की घटना दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 195 तक 17.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। केंद्र सरकार 2030 तक भारत को टीबी से मुक्त करे, जिसकी उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं।

क्या टीबी सच में खत्म हो चुकी है?

वर्ल्ड टीबी डे पर विशेष

डॉ. रूपेश मोदी

छाती रोग विशेषज्ञ एवं इंदौर चेस्ट सोसायटी के अध्यक्ष

एक समय था जब ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) को 'राजयक्ष्मा' या 'सफ़ेद प्लेग' कहा जाता था। इसे बीती सदी की बीमारी मान लिया गया था, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ अतीत की परछाई बन चुकी है, या यह अब भी हमारे भविष्य पर खतरा बना हुआ है? सच तो यह है कि टीबी अभी भी ज़िंदा है, और अगर हम लापरवाह हुए, तो यह आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकती है।

टीबी कोई नई बीमारी नहीं है। इसके प्रमाण हजारों साल पुराने कंकालों, मिस्र की ममियों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलते हैं। 1882 में जब रॉबर्ट कॉख ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की, तो यह समझ आया कि यह एक संक्रामक रोग है, जो हवा के जरिए फैलता है।

इसके बाद टीबी के खिलाफ वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बनीं, जिससे यह बीमारी काफी हद तक नियंत्रित हुई। लेकिन क्या यह खत्म हो गई? नहीं!

आज भी यह बीमारी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है और इसके नए, अधिक खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं।

टीबी क्यों और घातक हो सकती है?

आज टीबी से बचाव के लिए दवाएँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ कारणों से यह फिर से विकराल रूप ले सकती है-

1. **ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी** – दवाओं का गलत या अधूरा उपयोग बैक्टीरिया को और ताकतवर बना रहा है, जिससे दवाएँ असर नहीं कर रही हैं।
2. **अव्यवस्थित जीवनशैली** – कुपोषण, धूम्रपान, शराब और प्रदूषण इम्यूनिटी कमजोर कर रहे हैं, जिससे टीबी का खतरा बढ़ रहा है।
3. **लोगों की लापरवाही** – कई लोग इसे मामूली खाँसी समझकर इलाज में देर कर देते हैं, जिससे यह दूसरों तक फैलती रहती है।
4. **संक्रमण का बढ़ता दायरा** – भीड़भाड़, खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ और जागरूकता की कमी टीबी को फिर से महामारी बना सकती हैं।

क्या हम टीबी को अपने भविष्य से मिटा सकते हैं?

जवाब होगा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा-

समय पर जाँच करवाएँ – अगर लगातार दो हफ्ते से ज्यादा खाँसी, बुखार, वजन कम होना, रात में पसीना आना जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

पूरा इलाज करें – दवाएँ बीच में न छोड़ें, वरना बैक्टीरिया और ताकतवर होकर वापस लौट सकता है।

साफ-सफाई और पोषण का ध्यान रखें – अच्छी इम्यूनिटी टीबी से बचाने में मदद करती है।

टीबी मरीजों से भेदभाव न करें – यह एक इलाज़ योग्य बीमारी है, इसे सामाजिक कलंक न बनाएँ।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ – भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत मुफ्त इलाज और सहायता दी जा रही है।

टीबी को हमेशा के लिए मिटाना संभव है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। अगर हमने इसे हल्के में लिया, तो यह बीमारी फिर से हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। हमें इसे सिर्फ अतीत की परछाई बनाए रखना है, न कि भविष्य का खतरा!

कैसे खाते, पीते और सोते हैं अंतरिक्ष यात्री

विज्ञान

संजीव शर्मा

लेखक आकाशवाणी भोपाल में समाचार संपादक हैं।

भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के मंगलवार को सकुशल वापस लौटने से सब मंगल हो गया और तमाम तरह के संशय के बादल छट गए। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रहीं और 17 घंटे का सफर कर समंदर में उतरी और फिर सुरक्षित वहां पहुंच गईं जहां उन्हें नौ महीने पहले होना चाहिए था। इसके पहले का किस्सा हम सब जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को 5 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर एक टेस्ट मिशन के लिए भेजा गया था। यह मिशन मूल रूप से 8 दिनों का था, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। नतीजतन, उन्हें 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा, और वे 19 मार्च को धरती पर लौट पाईं।

इस सफलता के जश्न में आपके दिमाग में भी यह ख्याल आया होगा कि इस लंबे प्रवास के दौरान सुनीता और उनके साथी क्या खाते होंगे? कैसे खाते होंगे? उनकी दिनचर्या कैसे संचालित होती होंगी? सवाल वाकई गंभीर हैं क्योंकि जहां पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं और सब कुछ हवा में उड़ता रहता है, वहां ये तो संभव नहीं है कि अंतरिक्ष यात्री हमारी तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी का लुत्फ लें क्योंकि सब्ज़ी तो ठीक है लेकिन यदि चावल के दाने उड़ने लगे तो उनको इकट्ठा करना मुश्किल तो हो ही जाएगा बल्कि जानलेवा भी हो सकता है इसलिए यह सवाल उठना लाज़िमी है कि सुनीता विलियम्स एवं उनके साथी क्या और कैसे खाते थे ? दरअसल, अंतरिक्ष में यात्री विशेष रूप से तैयार किया गया खाना खाते हैं, जो पौष्टिक, हल्का, और स्टोर करने में आसान होता है। ये भोजन आमतौर पर सूखा, प्री-पैकेज्ड और वहां के वातावरण के अनुरूप होता है ताकि अंतरिक्ष के वातावरण में खराब न हो और गुरुत्वाकर्षण की कमी में भी आसानी से खाया जा सके। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण, भोजन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वह हवा में न तैरे। अंतरिक्ष यात्री इसे छोटे टुकड़ों में खाते हैं और खाने को पाउच या कंटेनर से सीधे मुँह में डालते हैं। यहां तक कि स्वाद के लिए नमक और मसाले भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं।

वैसे, मिशन की शुरुआत में सुनीता और उनकी टीम के पास ताजे फल, सब्जियां, रोस्ट चिकन, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थ भी थे। यह स्टॉक तीन महीने में खत्म हो गया। फिर उन्हें फ्रीज-ड्रायड यानि सूखे भोजन पर निर्भर रहना पड़ा। इस फ्रीज-ड्रायड भोजन को अंतरिक्ष स्टेशन के टैंक से पानी मिलाकर तैयार करना पड़ता था और यह पानी भी अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र को रिसाइकिल करके ही बनाया जाता था। चौंकिए मत, अंतरिक्ष में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन, सुनीता ठहरी आधी भारतीय तो बिना चटपटा खाए उनका मन कैसे लगता इसलिए वे अपने साथ समोसे जैसे भारतीय स्नैक्स भी ले गयी थीं ।

अब बात दैनिक क्रियाओं की- मसलन ब्रश करना, नहाना और मल मूत्र विसर्जन जैसे काम क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अंतरिक्ष में खाना ही नहीं, दाँत ब्रश करना भी पृथ्वी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण पानी और टूथपेस्ट हवा में तैर सकते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री इसे सावधानी से और विशेष तरीके से करते हैं। उनका ब्रश कुछ हमारी तरह ही होता है लेकिन पेस्ट ऐसा होता है कि उसे खा भी सकते हैं ताकि थूकना न पड़े और उस थूक या कुल्ले के उड़ने का खतरा न रहे। वैसे कुल्ला करने के लिए खास तरह का पाउच और तौलिया भी होता है जिसमें पानी बाहर निकलने का खतरा नहीं रहता। दरअसल, अंतरिक्ष स्टेशन पर पानी बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे बहुत संभालकर खर्च किया जाता है । अंतरिक्ष में स्नान करना पृथ्वी की तरह नहीं होता कि शावर चलाया और पूरे बाथरूम में घूम घूमकर नहा लिया। असल में वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण पानी बहता नहीं, बल्कि हवा में तैरने लगता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री पारंपरिक शावर या बाल्टी से नहाने की जगह विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। नहाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पानी से भीगा हुआ तौलिया या वेट वाइप्स दिए जाते हैं। ये तौलिये पहले से साबुन या खास सफाई के घोल से तैयार होते हैं। बालों को साफ करने के लिए उन्हें नो-रिंस शैम्पू यानि जिसे धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, इस्तेमाल करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक एक ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ धोने की सुविधा नहीं होती। इसलिए गंदे कपड़ों को सील बंद बैग में रखा जाता है और बाद में उन्हें धरती पर लाकर नष्ट कर दिया जाता है।

सबसे ज्यादा समस्या मल मूत्र विसर्जन को लेकर रहती है इसलिए इसके लिए भी विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। जैसा कि ऊपर भी मैंने लिखा है कि अंतरिक्ष स्टेशन में करीब 90 फीसदी पानी मूत्र से ही बनता है। इसके लिए अंतरिक्ष स्टेशन में खास तकनीक से मूत्र को साफ करके पीने योग्य पानी में बदला जाता है ।

अंतरिक्ष में यात्री पेशाब करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की कमी में काम करने के लिए बनाए गए हैं इसलिए तैरते हुए मूत्र से बचने के लिए इनमें सक्शन सिस्टम लगा होता है। यात्री इसे इस्तेमाल करने से पहले विधिवत प्रशिक्षण लेते हैं। कुछ यही स्थिति मल त्याग की होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण के बाद खास किस्म की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करना होता है। वह भी सक्शन सिस्टम पर आधारित होती है। हालांकि, अभी तक मूत्र की तरह मल को रिसाइकिल नहीं किया जाता लेकिन वैज्ञानिक इसको रिसाइकल करने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं ताकि इसका उपयोग खाद में बदलने या ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सके ।

यह सब पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है और सुनीता विलियम्स ही नहीं तमाम अंतरिक्ष यात्री इसका पूरी तत्परता,सजगता और सावधानी के साथ पालन करते हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि जरा सी चूक उनके पूरे मिशन को मुश्किल में डाल सकती है। यही कारण है कि पग पग पर सावधानी बरती जाती है। फिर चाहे, अंतरिक्ष यात्रियों को नौ दिन की बजाए नौ महीने तक अंतरिक्ष में रखना पड़े।

सड़क किनारे संचालित हो रहे शहर के साप्ताहिक बाजार

बेपटरी हो जाती है यातायात व्यवस्था, बार-बार लगता है जाम

संजय द्विवेदी,

बैतूल। शहर के साप्ताहिक बाजार सड़क किनारे पर संचालित है। जिससे न सिर्फ हादसों की संभावनाएं बनी रहती है, बल्कि सब्जी विक्रेताओं के सड़क किनारे तक दुकाने लगाने से बार-बार जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। हालांकि सड़क किनारे संचालित साप्ताहिक बाजारों को शिफ्ट करने और जाम की समस्या से निजात के लिए कई बार प्रयास हुए। यहां तक कि नगरपालिका ने कुछ हफ्ते तक चूने से मार्किंग कर सब्जी विक्रेताओं को सडक़ से पांच फीट अंदर बैठने की व्यवस्था भी बनाई थी, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकी और कुछ हफ्तों बाद ही बेपटरी हो गई है। परिणाम स्वरूप सडक़ पर जाम लगने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दे कि गंज क्षेत्र में बुधवार-शनिवार और कोठीबाजार-सदर क्षेत्र में गुरूवार-रविवार प्रति सप्ताह साप्ताहिक बाजार संचालित होते है। इन तीनों ही बाजार में ट्रॉफिक की समस्या बनी रहती है। खासकर शाम के समय ट्रॉफिक के हालात इतने बदत्तर हो जाते है कि लोगों को पैदल चलने के लिए भी जगह तलाशनी पड़ती है।

फाइलों में शिफ्टिंग का निर्णय, चूने की लाइन भी गायब: कुछ समय पहले नगरपालिका ने कोठीबाजार साप्ताहिक बाजार को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। जगह भी फाइनल हो गई थी। एक-दो हप्ते यहां बाजार भी लगा, लेकिन फिर सब्जी बाजार कोठीबाजार में लगने लगा। इसके बाद नगरपालिका ने सडक़ के दोनों किनारों पर चूने की मार्किंग डालना शुरू किया था। यह मार्किंग सडक़ से पांच फीट अंदर की तरफ डाली जाती थी। ताकि सब्जी विक्रेता चूने की मार्किंग के अंदर ही अपनी दुकानें लगाए, लेकिन सडक़ पर मार्किंग डालने बंद हुआ तो पुन: दुकानदार और सब्जी विक्रेता ठीक सडक़ के किनारे दुकानें लगाने लगे। इस स्थिति के चलते अब हर रविवार और गुरुवार को बाजार से निकलना मुश्किल होता है। वैसे अब तो सप्ताह के सातों दिन सब्जी विक्रेताओं की दुकानें सडक़ किनारे लगी देखी जा सकती है।

नपा यहां भी कर सकती है बाजार संचालन की व्यवस्था

नगरपालिका के पास सब्जी बाजार के संचालन के लिए खाली जमीन मौजूद है, लेकिन इस जमीनों का उपयोग साप्ताहिक बाजार लगाने नहीं किया जा रहा है। यदि नगरपालिका चाहे तो सदर में ओवरब्रिज के पास बैलबाजार में खाली जमीन पर सदर बाजार का संचालन कर सकती है, इसके अलावा गंज क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल को डिसमेंटल किए जाने के बाद काफी बड़ी जगह खाली हुई है। यहां भी सब्जी विक्रेताओं को बैठाया जा सकता हैं, लेकिन इंतजाम नहीं किए गए। कोठीबाजार क्षेत्र में राय साहब के बगले के पास खाली मैदान हैं, यहां भी बाजार लगाकर काफी जाम की समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

गंज सदर में सड़क किनारे बाजार

कोठीबाजार, गंज और सदर क्षेत्र में भी सालों से सडक़ किनारे ही साप्ताहिक बाजार का संचालन हो रहा हैं। इस वजह से यहां प्रति सप्ताह वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कोठीबाजार और गंज में लोगों को जाम की स्थिति का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां बाजार लगाने के लिए खाली जगह नहीं है, लेकिन इसका उपयोग बाजार क्षेत्र के लिए नहीं किया जा रहा है। सदर में भी साप्ताहिक बाजार सडक़ किनारे ही लगाया जाता है। पूर्व में यहां से सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर व्यवस्था बनाने के कोशिश की गई थी, लेकिन सब्जी विक्रेताओं को वह ज्यादा दिन रास नहीं आई और बाजार पुन: सडक़ पर आ गया।

रविवार गुरुवार लगता है जाम

शहर के साप्ताहिक बाजारों में लोकल व्यापारियों के अलावा आसपास ब्लाक से भी सब्जी विक्रेता और दुकानदार आते है। प्रत्येक बाजार में कम से कम 600 से एक हजार के ऊपर सब्जी और सामान की दुकाने लगती है। वहीं खरीदारी करने वालों की साप्ताहिक बाजार में काफी भीड़ रहती है। जिसके कारण सडक़ से लोगों का निकलना भी मुश्किल होता है। चौपहिया वाहनों की आवाजाही के कारण कई बार सडक़ पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। सबसे ज्यादा कोठीबाजार के गांधी प्रतिमा के पास और कमानी गेट पर शाम के समय ऐसे हालात बन जाते है कि कोई बड़ा वाहन या यात्री बस आ जाये तो लंबा जाम लग जाता है और वाहन रेंगते हुए निकलते है।

इनका कहना है -

बाजार को शिफ्ट करने की योजना है। विधायक जी के भी निर्देश है। जहां तक चूने की लाइन की बात है तो जब तक बाजार शिफ्टिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक चूने की लाइन डालकर दुकानदारों को बैठाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि वाहन चालकों और लोगों को आने-जाने में दिक्कते न हो।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

सड़क किनारे दुकान लगाने वालों पर पुलिस करेगी चालानी कार्रवाई

कोठीबाजार में सडक़ किनारे दुकाल लगाने वालों पर अब पुलिस चालानी कार्रवाही करेगी। पुलिस ने दुकानदारों को इस संबंध में पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी दुकानदार सडक़ पर दुकान न लगाये। कोतवाली थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया ने बताया कि यातायात व्यवस्था में जो भी दुकानदार बाधा बनेगा, उसे अब चालानी कार्यवाही का सामना करना ही पडेगा। बता दे कि कोठीबाजार में प्रति गुरूवार और रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार का संचालन किया जाता है। इन दिनों में दुकानदार अपनी दुकाने सडक़ तक लगा लेते है, जिससे बार-बार ट्रॉफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। हादसों का डर भी बना रहता है। हालांकि नगरपालिका ने बाजार को व्यवस्थित करने के लिए कई बार बाजार शिफ्ट करने की योजना बनाई। बाजार में चूने की लाइन डालकर व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन चंद हप्ते बाद व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर लौट आई। जिसके कारण आमजनों को ट्रॉफिक जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

माँ कर्मा जयंती पर साहू समाज द्वारा निकाली वाहन रैली

कलश यात्रा का हुआ जगह-जगह स्वागत

बैतूल। रविवार को साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा की जयंती के उपलक्ष में साहू समाज जिला बैतूल द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली। साहू समाज के राजा साहू ने बताया कि कलश यात्रा का जगह-जगह सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। कलश यात्रा के पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित साहू समाज के युवाओं द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों से होकर वाहन रैली निकाली गई। जिसमें समाज की आराध्य देवी माँ कर्मा जी की आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के युवा, वृद्ध एवं महिलाएं उपस्थित थी।

आमला में शहीद दिवस पर 154 यूनिट रक्तदान कर रचा नया कीर्तिमान

बैतूल। आमला में रविवार को बचपन प्ले स्कूल, एएचपीएस आमला, जनसेवा कल्याण समिति एवं निफा के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 154 यूनिट रक्तदान किया गया, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। यह शिविर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया और इसे स्वर्गीय पंकज उसरेठे एवं स्वर्गीय शशि टिकारे की स्मृति को समर्पित किया गया। आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य राहुल धेण्डे और नीरज बारस्कर ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी आमला के रक्तदाताओं ने शानदार उत्साह दिखाया। इस शिविर में रक्तदान करने वाले सभी 154 रक्तदाताओं को निफा की ओर से प्रशस्ति पत्र और विशेष ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

विश्व मांगल्य सभा की महिलाओं ने ली जल संरक्षण की शपथ, शहीदों को किया नमन

बैतूल। विश्व जल संरक्षण दिवस और शहीद दिवस के उपलक्ष्य में विश्वमांगल्यसभा द्वारा आयोजित नित्य उपक्रम सदाचार सभा में महिलाओं ने जल संरक्षण की शपथ ली और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर जल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की गई। जल है तो जीवन है विषय पर नारे और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। जल संरक्षण के उपायों पर रोचक खेल भी आयोजित किए गए, जिससे इस गंभीर विषय को मनोरंजक तरीके से समझाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विश्वमांगल्यसभा शाखा बैतूल की अध्यक्ष डॉ. विजेता चौबे ने जल संरक्षण के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं, उपाध्यक्ष श्रद्धा खंडेलवाल ने शहीदों की शौर्यगाथा को याद करते हुए नए भारत के निर्माण पर विचार साझा किए। सदाचार सभा का संचालन प्रांजल तल्हारकर ने किया। इस अवसर पर विश्वमांगल्यसभा शाखा बैतूलबाजार की संगठक रुपाली कमाविसदार और सहसंगठक सीता शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सचिव सोनाली वागद्रे, शामिनी देव, तूलिका पचौरी, वर्षा उमप, अर्चना हुद्दार और प्रीति क्षीरसागर भी प्रमुख रूप से शामिल हुईं। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं ने जल संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने और शहीदों की कुर्बानी को याद रखने का संकल्प लिया।

मुलताई पुलिस ने अलग-अलग प्रकरणों में फरार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

बैतूल। मुलताई पुलिस ने अलग-अलग प्रकरणों में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च को पीड़ित ने आरोपी अंकित पिता सुरेश उबनारे उम्र 21 साल निवासी चिखलीखुर्द के विरूध्द बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडछाड करने एवं जान से मारने कि धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी के विरूध्द धारा 74,75(1)(i),78, 351(3) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। घटना दिनांक के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी पतारसी की गई और गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त कर आरोपी के घर के सामने ग्राम चिखलीखुर्द से घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया। वहीं दूसरे प्रकरण में फोन पर परेशान करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अनिल पिता दशरथ पठाडे उम्र 30 साल निवासी भगसिंह वार्ड मुलताई को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मुलताई थाने में धारा 78,296,351(3) भारतीय न्याय संहिता का मामला पंजीबद्ध था। आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था। आरोपी की जानकारी प्राप्त होने पर घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को न्यायालय पेश किया गया।

कोतवाली पुलिस ने बोथरा मोबाइल शॉप में हुई चोरी का किया खुलासा

1 लाख 5 हजार 996 रुपये कीमत के 4 मोबाइल जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने बोथरा मोबाइल शॉप में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी के कब्जे से 1 लाख 5 हजार 996 रुपये कीमत के 4 मोबाइल जप्त किये है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 18 मार्च को अमित पिता शिखरचंद बोथरा, उम्र 42 वर्ष, निवासी चक्कर रोड बैतूल ने थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी श्री बोथरा मोबाइल शॉप, जो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स बैतूल में स्थित है, वहां से अज्ञात आरोपियों द्वारा दुकान का ताला तोडकर 59 एंड्रॉइड मोबाइल एवं 7000 रुपये नगद चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर धारा 331(4), 305, बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। और पुलिस टीम ने दुकान एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तथा बारीकी से जांच करने पर इनमें कुछ संदिग्ध युवक दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर संदिग्ध अरशद कुरैशी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री बोथरा मोबाइल शॉप का ताला तोडकर मोबाइल एवं नगदी चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी अरशद कुरैशी पिता असफाक कुरैशी उम्र 22 वर्ष निवासी गौली मोहल्ला, नागदेव मंदिर के पास, टिकारी बैतूल को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया, वहीं पकड़ए आरोपी अरशद से मिली जानकारी के आधार पर मामले के अन्य दो आरोपियों की तलाश सरगर्मी से जारी है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

इस मामले में पुलिस ने सूझबूझ एवं तत्परता दिखाते हुए 5 दिनो के भीतर ही चोर को पकड़ लिया। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी कोतवाली रविकांत डेहरिया, सउनि राजेश मालवीय, आरक्षक नितिन चौहान, प्र.आर. विनय पांडे, आरक्षक शिवकुमार, आरक्षक हर्षित डांगे, आरक्षक सोनू सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

गंज पुलिस ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद, अब तक चार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। गंज पुलिस ने व्यवसायी अशोक पवार की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 18 मार्च को रात्रि लगभग 9.15 बजे गंज क्षेत्र के हार्डवेयर व्यवसायी अशोक पवार की अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध आरोपी मृतक अशोक पवार की दुकान के बाहर टहलते और रेकी करते नजर आए थे। कुछ देर बाद उनमें से एक आरोपी दुकान में घुसा और अशोक पवार को गोली मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना के आधार पर थाना गंज में धारा 103(1), 3 (5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय पिता बलीराम भोसले उम्र 38 वर्ष, निवासी पोखर खुर्द, जिला खरगोन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। आरोपी अजय को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा भगूढाना क्षेत्र में एक नाली में फेंकने की बात स्वीकार की, जिसे पुलिस ने आरोपी की निषेध पर बरामद कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बता दे कि बैतूल पुलिस ने इस हत्याकांड में तीन आरोपी राजेश गिरी गोस्वामी पिता परसुराम गोस्वामी (उम्र 30 वर्ष), निवासी शेरपुर, थाना गैरवा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, विलेशगिरी पिता सेनगिरी महाराज (उम्र 40 वर्ष), निवासी पुरानी बिंदवारी, गांधीनगर, तहसील बांदा, उत्तर प्रदेश और भारत पिता दिनेश धोप (उम्र 23 वर्ष), निवासी पोखर खुर्द, थाना भीकनगांव जिला खरगोन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस कार्रवाही में निरीक्षक अरविंद कुमरे, थाना प्रभारी गंज, सउनि किशोरीलाल सल्लाम, आर. अनिरुद्ध यादव, आर. नवीन, आर. गजानंद वाडीवा, आर. मंतराम सरियाम, आर. मनोज कोलारे की सराहनीय भूमिका रही।

चूल्हे में गिरने से झुलसा बच्चा

बैतूल। ग्राम देहगुड़ में रविवार सुबह भोजराज नागल के 10 वर्षीय बेटे क्रिश के कपड़ों में आग लग गई। घटना उस समय हुई जब क्रिश अपने 4 वर्षीय छोटे भाई समीर के साथ चूल्हे के पास खेल रहा था। खेलते समय क्रिश अचानक चूल्हे में गिर गया। बच्चों की चीख सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्रिश को चूल्हे से बाहर निकाला और कपड़ों में लगी आग को बुझाया। परिजनों ने तत्काल साइखेड़ा पुलिस को सूचना दी। डायल 100 की गाड़ी मौके पर पहुंची और बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाने लगी। रास्ते में एंबुलेंस मिली, जिसमें बच्चे को शिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। सरकारी अस्पताल में बीएमओ डॉ. पंचम सिंह ने बताया कि क्रिश की छाती, हाथ और पेट का हिस्सा बुरी तरह जल गया है। उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

हादसों में दिवंगतों को बैतूल विधायक ने दी श्रद्धांजलि

परिजनों को 20-20 हजार रुपए की व्यक्तिगत नगद सहायता दी

बैतूल। विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने के बाद शनिवार को भोपाल से बैतूल आए विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा कर क्षेत्रवासियों से संवाद किया। भ्रमण के दौरान बैतूल विधायक ने दिवंगत जनों के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पितकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। गत दिनों इंडस्ट्रियल एरिया बैतूल स्थित एक इंडस्ट्री के हादसे में दिवंगत हुए कम्पनी गार्डन निवासी स्व.कैलाश पानकर, रामनगर निवासी स्व.दयाराम नरवरे सहित एक अन्य हादसे में दिवंगत हुए बुण्डाला निवासी संजय पाटिल के सुपुत्र स्व.राजकुमार पाटिल के निवास पर पहुचकर बैतूल विधायक नें दिवंगतो को श्रद्धांजलि देकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बधाया। बैतूल विधायक नें दिवंगतो के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की व्यक्तिगत आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की।

बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली

इंडस्ट्री हादसे मे दिवंगत हुए स्व.दयाराम नरवरे एवं स्व. कैलाश पानकर के परिजनों से बैतूल विधायक नें चर्चाकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक श्री खण्डेलवाल नें कहा कि इस दुख की घडी में वे हमेशा साथ खड़े रहेगें। उन्होनें दिवंगतजनो के बच्चो की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर कहा कि बच्चों की पढाई पर व्यय होने का खर्च वे वहन करेगे। इस दौरान भाजपा गंज मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा,कोठी बाजार मंडल अध्यक्ष विक्रम वैघ,बैतूल बाजार मंडल अध्यक्ष सुनिल पवॉर सहित परिजन और पार्टीकार्यकर्ता मौजूद रहे।

दर्ज संख्या बढ़ाने शिक्षक लगा रहे एड़ी चोटी का जोर

तेज गर्मी में शिक्षक घर-घर दे रहे दस्तक

बैतूल। स्कूलों का आगामी 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। जिसमें प्रवेश उत्सव मनाकर कक्षाएं संचालित की जाएगी। स्कूलों में कम दर्ज संख्या से शिक्षक परेशान दिख रहें हैं। ढोंडवाड़ा स्कूल के शिक्षक तेज गर्मी में भी स्कूल में अधिक दर्ज संख्या बढ़ाने के साथ व शाला त्यागी बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विगत एक सप्ताह से लगातार गांव-गांव घूमकर पालकों को आमंत्रण दे रहें हैं। शिक्षक मदनलाल डढोरे ने बताया कि सांवगा, ढोड़वाड़ा, नयेगांव, बाबई, सेलगांव में लगातार पालकों से संपर्क कर शासन की योजनाओं की जानकारी देकर शासकीय स्कूल में नामांकन के लिए प्रयास कर रहें हैं।

पुलिस अधिकारियों ने रात्रि में किया थानों का आकस्मिक निरीक्षण

सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा

बैतूल। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जिले के विभिन्न थानों का रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम ने थाना शाहपुर का रात्रि में औचक भ्रमण किया। दरअसल पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश कैलाश मकवाना द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि रात्रि 11 बजे से 2 बजे के मध्य अपने-अपने क्षेत्र के थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करें। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन मिथिलेश कुमार शुक्ला द्वारा बैतूल जिले के थाना शाहपुर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश ठाकुर उपस्थित रहे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना परिसर की साफ-सफाई, रजिस्टर संधारण, व्हीसीएनबी (वीसीएनबी), गुंडा रजिस्टर, निगरानी बदमाश रजिस्टर आदि की जांच की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के संबंध में यदि कोई मामला माफीनामा योग्य है तो उसे तैयार किया जाए और आवश्यक मामलों में हिस्ट्रीशीट तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। इसके अलावा, ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के अधिकतम उपयोग, समन एवं वारंटों के निष्पादन में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर खराब कैमरों को शीघ्र सुधारने के निर्देश भी दिए गए।

एसपी, एएसपी ने भी किया थानों का निरीक्षण

बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी सहित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। एसपी निश्चल एन झारिया ने आमला एवं मुलताई थाने का दौरा किया, वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी ने बैतूल बाजार थाना, एसडीओपी बैतूल सुश्री शालिनी परस्ते ने साईंखेड़ा थाना, एसडीओपी सारनी रोशन जैन ने सारनी थाना, एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मोर्या ने झल्लार थाना, एसडीओपी शाहपुर मयंक तिवारी ने चिचोली थाने का निरीक्षण किया।

अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन की धार शाखा ने मनाया फाग उत्सव

धार। अंतराष्ट्रीय इस्कॉन की जिला धार शाखा बंदी छोड़ बाबा के सामने फाग उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम भजन संध्या,उसके बाद इंदौर से पधारे सुदर्शन जी द्वारा उद्बोधन,फिर सभी पधारे भक्तजनों ने फूलों से होली खेली और सबसे अंत में महाप्रसादी का वितरण हुआ। जानकारी धार शाखा प्रमुख रणबीर दास ने दी ।

बाल संस्कार एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज

भोपाल (नप्र)। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित गीता परिवार द्वारा बाल संस्कार एवं बालिका सशक्तिकरण को समर्पित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज 24 मार्च को सिद्धेश्वरी माता मंदिर, 5 नंबर स्टॉप के पास, भोपाल में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मध्यांचल गीता परिवार प्रमुख प्रमिला माहेश्वरी दीदी मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। प्रमिला दीदी का दशकों का अनुभव, बाल संस्कार केंद्रों के सफल संचालन और बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा प्रेरणादायक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में उन्होंने बाल संस्कार वर्गों को एक सशक्त अभियान के रूप में विकसित किया है। कार्यशाला की प्रमुख विशेषताएँ देशभक्ति गीत एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, योगासन, हास्ययोग एवं एकाग्रता बढ़ाने के प्रयोग, ज्ञानेंद्रिय संवर्धन एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गीता परिवार पंचसूत्र का अभ्यास, कहानी-कथाकथन की कला एवं प्रायोगिक शिक्षण तकनीकें और मनोरंजनात्मक खेल एवं समूह गतिविधियाँ हैं। कार्यशाला सुबह 9:00 बजे से आरंभ होकर शाम तक चलेगी कार्यशाला का उद्देश्य मध्यप्रदेश में बाल संस्कार वर्गों के प्रभावी संचालन के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

सामाजिक जन कल्याण समिति का पारिवारिक मिलन समारोह संपन्न

बैतूल। शहीद भवन में रविवार 23 मार्च को सामाजिक जन कल्याण समिति द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश माखन झोड़, शिक्षक जगदीश लोखंडे और अजय मांडवे रहे। इस विशेष आयोजन में समिति के अध्यक्ष मानिक राव कापसे, सचिव दयाराम झरबडे, कोषाध्यक्ष मानकप्रसाद वाईकर, शिवदयाल चौकीकर, सूरज लाल मंडलेकर, शेषराव वाईकर, शेषराव नागले, द्वारका प्रसाद बिसंदरे, पांडुरंग वरवड़े और नत्थू प्रसाद चौकीकर मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत भंते दीपांकर द्वारा दीप प्रज्वलन और पूजा-अर्चना से हुई। सामाजिक जन कल्याण समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को साल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को पारितोषिक और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में समिति के अध्यक्ष मानिक राव कापसे ने समापन भाषण दिया और सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

बनेगा 50 बिस्तरों वाला अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 22 हजार करोड़ का प्रवधान किया : पटेल

सुबह सवेरे सोहागपुर। इस वर्ष प्रदेश भाजपा सरकार ने बजट में लगभग 22 हजार करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुनिश्चित किए हैं। इसी तारतम्य में सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय में 9 करोड़ 19 लाख रूपये की लागत से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसी विधानसभा के आदिवासी ग्राम में 65 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनता-जनार्दन को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। उक्त उद्गार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटैल ने भूमि पूजन के अवसर पर सामुदायिक अस्पताल सोहागपुर प्रांगण में कहें। इस अवसर

पर विशेष अतिथि सांसद दर्शनसिंह चौधरी, राज्य सभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, पूर्व विधायक सविता दीवान,भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश पटेल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह आदि मंचासीन थे। आपने आगे कहा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई है । आपने क्षेत्रीय विधायक की प्रशंसा करते कहा कि उनकी सक्रियता का प्रतिफल है कि क्षेत्र में उक्त सुविधा नागरिकों को प्राप्त होगी। इसी अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित कर रही है।इसी क्रम में सोहागपुर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सर्वसुविधायुक्त सिविल अस्पताल की सौगात मिली है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक, लैब, स्वास्थ्य कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था सहित कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आपने आगे कहा कि सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। कार्यक्रम को कई अतिथियों ने संबोधित किया।

इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी असवन राम चिरामन, सीएमएचओ, डॉ दिनेश देहलवार नर्मदापुरम,बीएमओ डॉ संदीप किरकेट्टा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी. एस. राजपूत, सीईओ, संजय अग्रवाल, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे।

एम्स भोपाल स्पोर्ट्स कमेटी द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान के स्पोर्ट्स कमेटी द्वारा इस सप्ताहांत 22 और 23 मार्च, 2025 को बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन खेल-कूद को प्रोत्साहित करने, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने और आपसी सामंजस्य को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। इस टूर्नामेंट में एम्स भोपाल के कर्मचारी, छात्र और संकाय सदस्य ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा, 'यह टूर्नामेंट एम्स भोपाल की खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का यह एक शानदार अवसर है। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, जिसमें कौशल, रणनीति और फुर्ती का अद्भुत समन्वय होता है। खेल गतिविधियाँ न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि मानसिक ताजगी और टीम भावना को भी विकसित करती हैं।' यह टूर्नामेंट स्पोर्ट्स कमेटी के कन्वेनर डॉ. मूरत सिंह यादव के निर्देशन में आयोजित किया गया।

मांगें नहीं मानी तो पेंशनर करेंगे प्रांतव्यापी आंदोलन

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला शाखा भोपाल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने उपस्थित पेंशनरों को पुष्पगुच्छ एवं गुलाल लगाकर स्वागत किया। होली मिलन के बाद की गई बैठक में उपस्थित पेंशनरों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आने वाले माह में प्रांतव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया। प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने समय पर महंगाई राहत नहीं देने पर प्रदेश शासन पर भेदभाव का आरोप लगाया वहीं उपाध्यक्ष शंभूनाथ मुखर्जी ने सरकार को पेंशनर विरोधी बताया। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रदेश के पेंशनरों को एकजुट होकर भोपाल में विशाल आंदोलन प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया । संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने फोन पर पेंशनरों को संबोधित कर होली की शुभकामनाएं दी एवं संगठित रहने का संदेश दिया । सक्सेना के अनुसार महंगाई राहत, कैशलेस चिकित्सा, वेतनमान का बकाया सहित पेंशनरों की सभी मांगों को लेकर आगामी माह में प्रांतव्यापी आंदोलन किया जाएगा बैठक में संगठन के मीडिया प्रभारी एस.के. शुक्ला, जिला शाखा के संरक्षक प्रमोद सिंगल, सर्वेश तिवारी उपाध्यक्ष हरेंद्र तिवारी, बैरसिया के अध्यक्ष हरि बल्लभ शर्मा भेल के अध्यक्ष पी.एन. उपाध्याय सहित कई पदाधिकारी ने सभा को संबोधित किया। मंच संचालन अनिल पांडे एवं राजेंद्र नायक ने किया ।

शहीद दिवस पर भाजपा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धासुमन अर्पित किये

धार। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की धार शहर स्थित प्रतिमा पर भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ,विधायक नीना वर्मा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने दुग्ध से अभिषेक कर माल्यार्पण श्रद्धांसुमन अर्पित कर माँ भारती के अमर सपूत वीर के क्रांतिकारी विचारों का स्मरण किया। भाजपा नेता डॉ शरद विजयवर्गीय ने कहा कि देश के इतिहास में आज का दिन बेहद अहम है। आज 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। सन् 1931 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत के युवा स्वतंत्रता सैनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी पर लटकाया था। आजादी की लड़ाई में हंसते-हंसते अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों की शहादत में यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि इस दौरान

भाजपा नेता डॉ शरद विजयवर्गीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, कॉलेज जनभागीदारी समिति अध्यक्ष दीपक बीड़कर,पुर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कालीचरण सोनवानीया, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, जिला पदाधिकारी मनीष प्रधान भाजपा ठाकरे नगर मंडल अध्यक्ष जयराज देवड़ा, पुर्व मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर,पुर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रावल,विधायक प्रतिनिधि शिव पटेल,राजेश डाबी, सोनिया राठौड़, तरुण सिसोदिया,लव प्रजापति, सुरेश प्रजापत,अंकित जैन, बाला भाऊ, भोला रौंदले, भय्यू राम, नमन रावल, गिरीश सोलंकी, रतन भाभर, आकाश वर्मा, विजय बारिया, दीपेंद्र ठाकुर, गौरव जाट, रिंकू मेंरवानी, नवीन भवर, भंवरलाल कुमरावत, कपिल श्रीवास्तव, चेतन पंडाग्रे, महेश कदम, विशाल राठौड़, हरीश आर्य, शांतिलाल शर्मा, देवांग पवार, कमलेश बिजवा, सुभम राठौड़, दिनेश चौहान,केशव अग्रवाल, सौरभ त्रिपाठी,सनी चौहान, संदीप यादव, मोहन यादव,रवि देवासकर, कुंदन भूरिया, सोनू गावड़े, मनोज प्रजापत,सहित भाजपा नगर मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

छत से गिरे मजदूर की मौत

बैतूल। बैतूल के विवेकानंद वार्ड में रविवार दोपहर एक मजदूर छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिराम धुर्वे के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हरिराम अपने घर की छत से अचानक नीचे गिर गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई।

मानतुंगगिरी तीर्थ पर मनाई भगवान आदिनाथ की जयंती, अभिषेक किया

धार। दिगंबर जैन मंदिर मानतुंगगिरी तीर्थ पर रविवार को भगवान आदिनाथ की जयंती मनाई गई। मुनि श्री विश्वमित्रसागर जी महाराज एवं मानतुगागिरी संचालिका चंद्रमति माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर में से आदिकाल के प्रथम तीर्थंकर थे। उनका जन्म अयोध्या में हुआ तथा दीक्षा प्रयागराज संगम तट के निकट हुई तथा भगवान आदिनाथ

ने चित्रकूट में अपनी तपस्या पूर्ण की और उनका निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ। तभी से हम प्रथम तीर्थंकर के रूप में उनकी जयंती मनाते आ रहे है। हमें आदिकाल के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर की जयंती मनाने का आज फिर से गौरव मिला है। हम उनके धार्मिक इतिहास को समझें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने बड़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयाई बनाएं। मीडिया प्रभारी सुभाष जैन ने बताया कि उनकी जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान भगवान के अभिषेक हुए तथा शांति धारा करने का लाभ किशोर राजकुमारी जैन को मिला। इसके अतिरिक्त मूल भगवान की शांति धारा करने का लाभ नरेश कुमार श्रेणिक कुमार गंगवाल को मिला। सौधर्म बनने का लाभ अनिल राजेश्वरी जैन ने लिया। भक्तामर मंडल विधान की पूजन के दौरान पांच कलश विराजित किए गए जिसका लाभ शशि गंगवाल, राजकुमारी जैन, मीना जैन, पदमा गंगवाल, कांति जैन ने लिया। प्रारंभ में दीप प्रज्जवलन आकाश जैन ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेश गंगवाल ने किया। संचालन कोषाध्यक्ष किशोर जैन तथा सहसचिव मौसम झांझरी ने किया।

संत के अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय हिंदू सेना ने निभाया धर्म और कर्तव्य

पुलिस की सहमति के बाद संत समाज की उपस्थिति में किया अंतिम संस्कार

बैतूल। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, और जिसका कोई नहीं होता, उसका खुद ईश्वर होता है। इस कहावत को राष्ट्रीय हिंदू सेना ने चरितार्थ कर दिखाया जब उन्होंने महान योगाचार्य और संत स्वामी दयानंद ब्रह्मचारी का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मां ताप्ती नदी के तट पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय सहित संगठन के सभी पदाधिकारियों ने परिवार की तरह सेवा करते हुए संत का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने स्वामी जी को मुखाग्नि दी और उनकी अस्थियों का विसर्जन मां ताप्ती नदी में किया गया। यह भावुक क्षण देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने यह साबित कर दिया कि सेवा ही सच्चा धर्म है और महान संत को विधिपूर्वक विदा कर एक प्रेरणादायक उदाहरण

प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद ब्रह्मचारी का बैतूल जिला अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। पांच दिन पूर्व उन्हें पैरेरिक्स अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें आमला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां उपचार के दौरान 23 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदेश संयोजक पवन मालवीय ने बताया कि स्वामी जी की तबीयत खराब होने पर संत दिलीप दुर्वासा पूरी, प्रखर सोनपुरे और बजरंग दल के नगर सह संयोजक अंशुल सोलंकी ने उन्हें आमला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से गंभीर स्थिति में उन्हें बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनके उपचार की जिम्मेदारी संत दिलीप दुर्वासा पूरी संभाल रहे थे।

बौद्ध महासभा के व्यक्तित्व विकास शिविर में जिलेभर से जुटे अनुयायी

आदिवासी मंगल भवन में संपन्न हुआ विशेष शिविर

बैतूल। 23 मार्च रविवार को भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर आदिवासी मंगल भवन में संपन्न हुआ। इस शिविर में जिलेभर से बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। आयोजन दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय संरक्षक महाउपासिका मीरा ताई अंबेडकर और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आयुष्मान भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव एवं केंद्रीय शिक्षक बी एच गायकवाड़ रहे। शिविर की शुरुआत पूज्य भंते दीपांकर द्वारा बुद्ध वंदना और त्रीशरण पंचशील वाचन से हुई। विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे, प्रदेश महामंत्री मेजर उत्तम प्रधान इंदौर, प्रदेश सचिव राजकपुर कांबड़े बालाघाट और प्रदेश सचिव शंकरराव शेषकर

बैतूल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई बैतूल के अध्यक्ष अधिवक्ता नामदेव नागले ने की। शिविर में जिला, तहसील, नगर और ग्राम इकाइयों के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और धम्म अनुयायी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षक बी एच गायकवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी को बुद्ध के धम्म अनुसार आचरण कर संस्कारी समाज निर्माण में योगदान देना चाहिए। शिविर का सफल संचालन तहसील महासचिव जसवंती चौकीकर और कोषाध्यक्ष गीता नागले ने किया। आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष काशीनाथ वाघमारे ने किया, जबकि समापन इंजीनियर प्रकाश उबनारे ने किया।

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने जिला इकाई गठित

बैतूल में लघु उद्योग भारती ने ली उद्यमियों की बैठक

बैतूल। जिले में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग भारती संगठन ने उद्यमियों की बैठक लेकर संगठन के कार्यों की विस्तार जानकारी दी और जिला इकाई का गठन किया। जिसमें उद्योगपति अंबेश बलवापुरी को जिला संयोजक एवं ऋषि वर्मा को सहसंयोजक बनाया गया है। बैठक में जिले में स्थापित उद्योगों को लेकर चर्चा की गई जिसमें चालू उद्योग और बंद उद्योगों पर विस्तृत जानकारी ली गई। बैठक में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय सदस्य उमा शर्मा, मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष जीसी सेठिया, मध्य भारत प्रांत सचिव पुरूषोत्तम कौशिक उपस्थित थे। देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग भारती संगठन का गठन किया गया है। यह संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्य कर रहा है। संगठन के अखिल भारतीय सदस्य उमा शर्मा ने बताया कि संगठन की पूरे देश में 11 सौ इकाईयां हैं और 56 हजार सदस्य जुड़े हुए हैं। लघु उद्योगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय में बनाई गई समितियों में संगठन के सदस्य शामिल हैं। और सरकार के

द्वारा लघु उद्योगों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए समिति के सदस्य सुझाव देते हैं जिसमें लघु उद्योगों में आने वाली परेशानियों का निराकरण कराया जाता है।

जिले के उद्योगों पर हुई चर्चा

जिले में 137 उद्योग स्थापित है। इनमें से 90 उद्योग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं इसके अलावा 47 उद्योग किन्हीं कारणों से बंद हैं। जिले के लघु उद्योगों को लेकर बैठक में उपस्थित उद्योगपति मुकेश खण्डेलवाल, अंबेश बलुवापुरी, वीरेंद्र चौहान, पीयूष तिवारी, सतीष बडोनिया, राजा साहू, अब्दुल हक सहित अन्य ने चर्चा करते हुए उनको आने वाली परेशानियों की जानकारी लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों को दी। लघु उद्योग भारती ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार की समितियों में इन्हें रखने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रांत के अध्यक्ष डीसी सेठिया ने कहा कि हम लोग भोपाल में बैठकर उद्योगपतियों की हर समस्या के निराकरण के लिए तैयार हैं लेकिन आपको स्वयं भोपाल आकर उसकी समस्या और निराकरण के बारे में लिखित में अवगत कराना पड़ेगा ताकि हम शासन स्तर पर निराकरण का प्रयास कर सकें।

जिला इकाई का हुआ गठन

बैठक में सर्वसम्मति से उद्योगपति अंबेश बलुवापुरी को लघु उद्योग भारती की जिला इकाई का संयोजक मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही सेम वर्मा के पोते युवा उद्योगपति ऋषि वर्मा को सहसंयोजक बनाया गया है। लघु उद्योग भारती के मध्य भारत प्रांत सचिव पुरूषोत्तम कौशिक ने बताया कि जिला इकाई के अन्य पदाधिकारियों का चयन बाद में किया जाएगा। बैठक में मुकेश खण्डेलवाल, अंबेश बलुवापुरी, ऋषि वर्मा, नितिन खरावे, पारितोष खरावे, सुनील खरावे, नामदेव चढ़ोकार, वीरेंद्र चौहान, पर्व बलुवापुरी, लक्ष्मीकांत यादव, मोछल चावड़ा, राहुल अग्रवाल, धीरज मंडलेकर, शुभम मेश्राम, भारत सिंह ठाकुर, राजा साहू, अब्दुल हक, रोहित थारवानी, सतीष बडोनिया, पीयूष तिवारी, श्री विश्वकर्मा, आशीष राठौर, मोहन यादव, श्रवण मालवीय, राधेश्याम विश्वकर्मा, राहुल पटेल, तुलसी रामपते, अमित झाम, राधे मालवीय, सुनील धोटे, जमील खान सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे।

॥ मंदिरम् ॥

64

सिंहनाथ मंदिर, ओडिशा

सिंहनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ओडिशा के कटक जिले के बडम्बा तहसील में गोपीनाथपुर गांव के पास महानदी नदी के एक द्वीप पर स्थित है। आदिशंकराचार्य ने मंदिर के निर्माण में पंचायतन वास्तुकला का अभ्यास किया था। मंदिर के चारों ओर विष्णु, गणेश, सूर्य और महिषमर्दिनी को समर्पित मंदिर हैं। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसका योनिपत्र धरती से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला के पंचरथ देउल के प्रारंभिक विकास को दर्शाता है। सर्वेक्षण के अनुसार, मंदिर नौवीं शताब्दी ई. की शुरुआत का है। मंदिर में मूर्तिकला के पैनल और सजावटी रूपांकनों के साथ जटिल नक्काशी की गई है। ब्रह्मा, कार्तिकेय, विष्णु, पार्वती, लिंग पूजा की मन्नत वाली स्लैब, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा और लकुलीसा की छवियां परिसर की दीवार पर पाई जा सकती हैं।

एमपी में थमेगा बारिश-ओले का दौर, पारा बढ़ेगा

तीन दिन में होगी 4 डिग्री तक बढ़ोतरी; 25 मार्च से नए सिस्टम का असर

भोपाल। मध्यप्रदेश में ओले-बारिश और आंधी का दौर रविवार से थम जाएगा। वहीं, अगले 3 दिन तक पारे में बढ़ोतरी होगी। पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। रविवार से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दो दिन बाद प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में मौसम का मिला-जुला असर दिखाई दिया।

भोपाल, इंदौर-उज्जैन में तीखी धूप रही तो शहडोल, रीवा, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर आदि जिलों में ओले, बारिश और आंधी चली। शहडोल के तितरा गांव में 55 वर्षीय महिला रमसखिया केवट की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। सीधी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। जिससे चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। भोपाल में शनिवार सुबह से ही गर्मी का असर देखा गया। इस वजह से अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी ऐसा ही मौसम रहा। इससे पहले शुक्रवार-शनिवार

को प्रदेश में बारिश और आंधी की स्थिति बनी रही। कहीं ओले गिरे तो कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सतना, कटनी, सिंगरौली, दमोह, पन्ना, डिंडौरी, उमरिया, सागर, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, रीवा में बारिश और आंधी चली। 55 से अधिक शहर या कस्बों में मौसम का असर देखा गया। सागर, उमरिया समेत कई जिलों में ओले भी गिरे। वहीं, सिंगरौली में 54 किमी, रीवा में 39 किमी, जबलपुर में 34 किमी, मंडला-सागर में 30 किमी और छिंदवाड़ा में 28 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली।

मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के आखिरी दिन यानी, 27 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में लू भी चल सकती है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। बता दें कि मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है।

चंबल में पर्यटक बढ़ाने के लिए ऊंट सफारी की तैयारी

अटेर किले से पुल तक बालू में तैयार होगा ट्रैक, अप्रैल-मई तक प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना

भोपाल। चंबल नदी के तट पर ऊंट सफारी शुरू करने की तैयारी है। हालांकि इसके लिए अभी ईको-पर्यटन समिति का गठन और ऊंट सफारी के लिए तय किए जाने वाले किराए पर निर्णय लिया जाना बाकी है। योजना अनुसार काम चला तो प्रोजेक्ट अप्रैल से मई माह के बीच शुरू किया जा सकता है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सफारी का रास्ता 10 किमी रहेगा। इसके विकसित होने से ग्रामीणों को रोजगार मिल सकेगा। फॉरेस्ट विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है।

रेंजर बसंत शर्मा ने बताया कि ऊंट सफारी के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अप्रैल से मई के बीच इस प्रोजेक्ट को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे एक ओर चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ऊंट पालकों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। चंबल नदी के किनारे फैली महीन, भुरभुरी बालू समुद्र तट जैसा अहसास कराती है, लेकिन संसाधनों की कमी और लोगों में

व्याप्त भय के कारण पर्यटक इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। वहीं, अटेर पुल के निर्माण से अब बाहा, जैतपुर और आगरा जाने वालों के लिए एक नया मार्ग उपलब्ध हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में यूपी और एमपी की सीमा से होकर गुजरने वाले पर्यटकों को अटेर का किला और चंबल सफारी आकर्षित कर सकता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, ऊंट सफारी के लिए अटेर पुल से चंबल किनारे होते हुए देवालय तक का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सफारी वापस इसी मार्ग से लौटेगी। इस दौरान पर्यटक बीहड़ की प्राकृतिक सुंदरता, चंबल नदी का मनोरम दृश्य और स्वच्छ वातावरण का आनंद उठा सकेंगे।

सफर लगभग दस किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा, पर्यटकों की सुरक्षा, खानपान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। चंबल क्षेत्र के कई गांवों में किसान परंपरागत रूप से ऊंटों का पालन करते आए हैं। पहले ऊंटों का उपयोग परिवहन और सामान ढोने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इन ऊंट मालिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। इसके चलते कुछ लोग ऊंटों का उपयोग अवैध गतिविधियों, जैसे कि लकड़ी और रेत की तस्करी में करने लगे हैं। ऊंट सफारी के जरिए इन ऊंट मालिकों को एक ऑप्शनल और स्थायी रोजगार देने की पहल की जा रही है।

प्रदेश में 5 केन्द्रीय पुस्तकालयों का हो रहा संचालन

भोपाल। प्रदेश में नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5 केन्द्रीय पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही भोपाल के जीटीबी कॉम्प्लेक्स में विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान से स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी (पूर्व ब्रिटिश लाइब्रेरी) का संचालन किया जा रहा है। इन पुस्तकालयों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की भी सुविधा दी जा रही है। शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल को सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तकालय साहित्यिक पुस्तकों का भंडार भी है। पुस्तकालय में न्यूनतम शुल्क पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्तमान में पुस्तकालय में करीब एक लाख से अधिक पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभिन्न मासिक पत्रिका, समाचार पत्र, इंटरनेट सुविधा, निःशुल्क सेमिनार की सुविधा भी उपलब्ध है। पुस्तकालय के 3 अध्ययन हॉल में प्रतिदिन औसत रूप से 600 छात्र-छात्राएं बैठकर अध्ययन करते हैं। इस वर्ष मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पुस्तकालय का अनुरक्षण एवं विकास कार्य किया गया है। पुस्तकालय में अध्ययन सुविधाओं के लिये 32 केबिन

- **पुस्तकालयों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की सुविधा**
- **स्कूल शिक्षा विभाग पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण पर कर रहा है कार्य**

मॉडल स्टडी रूम का विकास लोक शिक्षण संचालनालय के आवंटित बजट से किया गया है। पुस्तकालय में महिला स्व-सहायता समूह को 'दीदी कैंटीन' के संचालन का कार्य दिया गया है। अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इंदौर 60 वर्ष पुराना हैरीटेज भवन है। 'पुस्तकें बुलाती हैं' अभियान के अंतर्गत इस पुस्तकालय से अब तक 17 हजार से अधिक विद्यार्थी पुस्तकालय से जुड़ कर पुस्तकालय का भ्रमण कर चुके हैं। पुस्तकालय में प्रति 15 दिवस के अंतराल में एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन दिये जाने की सुविधा निर्धारित की गई है। यहां लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी प्रशिक्षण लेने भी आते हैं। शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में आने वाले छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत सामान रखने के लिये 190 से अधिक क्षमता वाले लॉकर रैक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आवंटित बजट से क्रय किया गया है। पुस्तकालय की स्वशासी समिति की बैठक के लिये निर्णय अनुसार पुरानी सदस्यताओं को संशोधित कर 13 प्रकार की नई सदस्यताएं प्रारंभ की गई हैं। पुस्तकालय की संपूर्ण गतिविधियां भी डिजिटल रूप में प्रारंभ कर दी गई है। पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिये नवीन सुविधाओं के साथ कॉम्पिटिशन कॉर्नर प्रारंभ किया गया है।

आलोट विधायक को बीजपी ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण के मामले में विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था

भोपाल। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को प्रदेश भाजपा ने शो- काज नोटिस जारी किया है। चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों की स्थायी अधिग्रहण को लेकर अपने ही सरकार को घेरा था। सरकार को अपने ही विधायक के कारण बैक फुट पर आना पड़ा था। मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची, इसके बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से चिंतामणि मालवीय को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से जारी हुए नोटिस में लिखा गया है कि चिंतामणि मालवीय के ताजा बयानों और कृत्यों की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। चिंतामणि मालवी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है।

बजट पर बोलते हुए आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा- मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपए उज्जैन सिंहस्थ के लिए रखे हैं, उज्जैन उन पर अभिमान करता है। उज्जैन उनको अपना नेता मानता है, उज्जैन को गर्व है कि मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री उज्जैन से है। लेकिन, आज उज्जैन का किसान बहुत डरा और परेशान है। क्योंकि, सिंहस्थ के नाम पर उसकी जमीन पहले केवल 3-6 महीनों के लिए अधिग्रहित की जाती थी लेकिन आज उन्हें स्थायी अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है। पता नहीं किस अधिकारी ने यह विचार रखा है कि, स्पिरिचुअल सिटी (आध्यात्मिक नगरी) बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि स्प्रिचुअलिटी किसी सिटी में नहीं रहती है। वह तो त्याग करने वाले लोगों से होती है। हम कांक्रीट के भवन बनाकर स्पिरिचुअल सिटी नहीं बना सकते। इस बीच तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा- धन्यवाद डॉ. चिंतामणि मालवीय जी और मेरे दोनों साथी सतीश जी और अनिल जैन साहब। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि, उज्जैन के किसानों को बचाने के लिए हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें। परमार के बाद डॉ चिंतामणि मालवीय ने कहा- इसके पीछे उज्जैन के किसानों को आशंका है कि कॉलोनाइजर्स और भू-

माफिया का यह षड्यंत्र है। पैसा प्रतिभा से कमाया जाता है और जो जितना प्रतिभाशाली होता है, उतना ही धनवान भी होता है, ऐसा माना भी जाता है। चिंतामणि मालवीय ने कहा- हम तो पानी के बुलबुले हैं, भोर के सितारे हैं, लेकिन सिंहस्थ पांच हजार वर्षों तक चलेगा। जब तक इस देश में हिन्दू है और विश्व में कहीं भी हिन्दू हैं, सिंहस्थ चलेगा। हम सिंहस्थ की जमीन का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकते कि उससे बड़ा नुकसान हो जाए। मालवीय ने कहा- मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आता है कि 'ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई' कहीं यह न हो कि हम सिंहस्थ की जमीन को हमेशा-हमेशा के लिए खो दें।

यह उन अधिकारियों के लिए भी है, जो इस तरह की सलाह देते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, जिन्होंने जमीन नहीं देखी है। सिंहस्थ तंबुओं में होता है, वह बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं। कॉलोनाइजर्स को लाभ देना चाहते हैं। चिंतामणि मालवीय और महेश परमार के बाद उज्जैन उत्तर के बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा- हमारी सरकार ने अन्य धार्मिक चेतना स्थलों को श्री देव महालोक सलकनपुर, संतश्री रविदास महालोक सागर, श्री रामराजा महालोक ओरछा और ओंकारेश्वर महालोक के निर्माण के साथ-साथ ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत संस्थान को विकसित करने जा रही है। इस प्रकार हमारी सरकार संस्कृति और सनातन विचारों को भारत को विश्व के उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम कर रही है।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

क्या साय मंत्रिमंडल का विस्तार अगले महीने होगा ?

माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल अप्रैल में हो जाएगा। चर्चा है कि इस विस्तार में कुछ नए चेहरे आएंगे तो कुछ पुराने की विदाई हो सकती है। साय मंत्रिमंडल में अभी मंत्री के दो पद खाली हैं और हरियाणा फार्मूला लागू हुआ तो तीन की गुंजाइश है। साय मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें कई महीनों से चल रही हैं। लोकसभा के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी निपट गया, लगता है अब मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त निकल जाएगा। चर्चा है कि ख़राब परफॉर्मेंस और विवादों में घिरे कुछ मंत्रियों को ड्राप किया जा सकता है। भाजपा विधायकों में मंत्री बनने के लिए एक अनार सौ बीमार वाली कहावत चल रही है। कई नए और पुराने विधायक मंत्री बनना चाहते हैं। रायपुर जिले से मंत्री बनने की दौड़ में राजेश मूणत,पुरंदर मिश्रा और सुनील सोनी हैं तो बिलासपुर से अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक का नाम चर्चा में है। दुर्ग से गजेंद्र यादव का नाम सुर्ख़ियों में है। बस्तर से विक्रम उसेंडी का नाम कुछ लोग उछाल रहे हैं। सरगुजा संभाग से पुराने और नए विधायक मंत्री बनने के इच्छुक बताए जाते हैं। अब देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कुछ नेताओं को अगले माह निगम-मंडल की कुर्सी मिल जाएगी। चर्चा है कि संगठन के कुछ पदाधिकारियों को सरकारी पद मिल सकता है। इसके बाद प्रदेश संगठन में भी कुछ बदलाव होगा। खबर है कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव की नई टीम बन जाएगी।

रायपुर जिला पंचायत पर अंतत : भाजपा का कब्जा

रायपुर जिला पंचायत पर भाजपा ने आखिरकार कब्जा कर लिया। बताते हैं रायपुर जिला पंचायत में भाजपा का स्पष्ट बहुमत नहीं था, पर साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाकर अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवा लिया और कांग्रेसी देखते रह गए। भाजपा ने जोगी कांग्रेस से जुड़े संदीप यदु को अपने साथ शामिल कर लिया और बाकी पर दबाव बना दिया। रायपुर जिला पंचायत में गणित नहीं बैठने के कारण दो बार चुनाव को टालना भी पड़ा और जब गणित फिट बैठ गया और केमेस्ट्री मिल गई तो भाजपा ने चाल चल दी। कहते हैं एक सदस्य ना-नुकुर कर रहा था, पर अतिक्रमण दस्ता को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर उन्हें सरेंडर करा दिया गया। वैसे सुकमा में भाजपा का गणित काम नहीं आया और कांग्रेस की प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई।

वन विभाग की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी

खबर है कि पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति के खिलाफ अब आईएफएस सुधीर अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 1988 बैच के आईएफएस सुधीर अग्रवाल 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव को पीसीसीएफ बनाए जाने के खिलाफ पहले कैट गए, फिर बिलासपुर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने इसी महीने सुधीर अग्रवाल की याचिका को ख़ारिज कर अपैक्स स्केल पद पर श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वैध ठहराया। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल ने श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे। श्रीनिवास राव को भूपेश बघेल के राज में पीसीसीएफ बनाया गया। विष्णुदेव साय की सरकार में भी उन्हें बनाए रखा गया। सरकार बदलने के बाद पीसीसीएफ बदलने की कयास लगी थी,पर बदलाव हुआ नहीं और हाईकोर्ट ने श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। हवा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुधीर अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। कहते हैं श्रीनिवास राव की नियुक्ति के खिलाफ कुछ और वरिष्ठ अफसर कैट गए थे, पर वह मामला अभी कैट में ही पेंडिग है।

रेत से तेल निकालने के फेर में विधायक जी

कहते हैं राज्य के एक भाजपा विधायक रेत से तेल निकालने के चक्कर में हैं। इसके लिए अपने जिले में अपनी पसंद के अफसर को हाल ही में माइनिंग अफसर बना कर लाए हैं। बताते हैं विधायक बनने से पहले नेताजी कई रेत ठेका चलाते थे। इस कारण रेत ठेका में उन्हें मुनाफा नजर आता है। विधायक जी जिसे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जिले में अभी रेत खनन का काम शुरू नहीं हुआ है,पर विधायक जी काम शुरू होने से पहले गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है। कहते हैं जिले के कलेक्टर साहब भी विधायक जी की मंशा को भांप गए हैं और बर्रे छत में हाथ डालने की जगह अपने को कोसो दूर कर लिया है। अब देखते हैं विधायक जी की रणनीति कितनी कारगर होती है।

डीजीपी के लिए यूपीएससी को गया पैनल

खबर है कि छत्तीसगढ़ के परमानेंट डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को यूपीएससी को पैनल भेज दिया। पैनल में प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम के अलावा पवनदेव, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता का नाम है। गौतम के साथ ये अधिकारी भी डीजी स्तर के हैं। अशोक जुनेजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने चार फ़रवरी को अरुणदेव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाया है। यूपीएससी की अनुशंसा के बाद छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिलेगा। परमानेंट डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल होगा। प्रभारी डीजीपी के नाते परमानेंट डीजीपी के मजबूत दावेदार अरुणदेव गौतम हैं, पैनल में शामिल तीनों भी सशक्त दावेदार हैं। अब देखते हैं यूपीएससी किसके नाम पर टिक लगाता है।

कुलदीप जुनेजा हुए मजबूत

कहा जा रहा है कि पार्षद आकाश तिवारी की कांग्रेस में वापसी से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के हाथ मजबूत हुए हैं। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने आकाश तिवारी को टिकट नहीं दिया था। चर्चा है कि कुलदीप जुनेजा के समर्थक होने के कारण कांग्रेस ने आकाश तिवारी को टिकट नहीं दिया, जबकि आकाश पिछली बार उसी वार्ड से पार्षद थे। आकाश तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़े और विजयी रहे। कुलदीप जुनेजा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान देकर संगठन के निशाने में हैं और उन पर निलंबन की तलवार लटक रही है, ऐसे में आकाश तिवारी की कांग्रेस में वापसी से कुलदीप जुनेजा का पलड़ा भारी हो गया है। बताते हैं कुलदीप जुनेजा पिता-पुत्र (आनंद कुकरेजा और अजीत कुकरेजा) की कांग्रेस में वापसी से मुखर हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अजीत कुकरेजा कांग्रेस से बगावत कर रायपुर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कुलदीप जुनेजा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। चर्चा है कि कुलदीप अपनी हार का बड़ा कारण अजीत को मानते हैं।

विपक्ष की भूमिका में रहे भाजपा के कुछ विधायक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च को समाप्त हो गया। सदन तय कार्यक्रम के अनुसार ही चला, लेकिन इस बार सदन में विपक्षी सदस्यों के मुकाबले भाजपा के कुछ सदस्यों को ज्यादा आक्रामक देखा गया। भाजपा के कई सदस्य मंत्रियों को घेरने में परहेज नहीं किया। कई मौकों पर भाजपा सदस्यों और मंत्रियों के बीच गर्मागर्म बहस भी देखी गई। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उछालकर सदन का माहौल दो दिन गर्म रखा। बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की भूमिका हेडमास्टर जैसी रही। कई मौकों पर उन्होंने मंत्रियों को सवालों में घिरने से बचाया, तो कई मौकों पर जवाब न आने पर सख्त रुख भी अपनाया। कुछ विधायकों को नसीहत भी दी।

मातहत लेंगे वरिष्ठों का इंटरव्यू

खबर है कि 26 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए मातहत अपने वरिष्ठों का इंटरव्यू लेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पूर्व डीजीपी डी एम अवस्थी व अशोक जुनेजा के अलावा कई रिटायर्ड आईएएस ने आवेदन किया है। मुख्य सूचना आयुक्त के दावेदारों को 26 मार्च को सर्च कमेटी के सामने उपस्थित होना है। सर्च कमेटी एसीएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें कुछ प्रमुख सचिव भी हैं। बताते हैं दावेदारों का इंटरव्यू लेकर सर्च कमेटी पैनल बनाएगी। फिर इस पैनल के नामों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।